असली आज़ादी ■ वर्ष: 21, अंक: 232 ■ दमण, गुरुवार 04, जून 2026 ■ पृष्ठ: 8 ■ मूल्य: 2 रु ■ RNI NO-DDHIN/2005/16215 ■ संपादक- विजय जगदीशचंद्र भट्ट

dadra & nagar haveli daman & diu

सत्यमेव जयते

नया भारत

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव प्रशासन

द्वारा

माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेंद्र मोदी

का हार्दिक स्वागत है।

दिनांक: शुक्रवार, 5 जून 2026 | समय: सायं 5:00 बजे से

: सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल :

स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स ग्राउंड, दमण

सीधा प्रसारण: मालाला ऑडिटोरियम, दीव

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री प्रफुल पटेल
माननीय प्रशासक
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव और लक्षद्वीप

₹2,970 करोड़

की लागत से 56 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

5 जून को पीएम मोदी सूरत से करेंगे 18,777 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

■ जीआईडीसी अंतर्गत भरूच में 894 करोड़ रुपए से अधिक के तथा वलसाड में 169.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे ■ दहेज पीसीपीआईआर में प्रदूषित जल के प्रभावी निस्तारण के लिए 474.61 करोड़ रुपए के एफ्लुएंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा ■जंबूसर बल्क ड्रग पार्क में 274.96 करोड़ रुपए की लागत से रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क तथा सेंट्रल ड्रेन की सुविधाओं से फार्मा क्लस्टर के विकास को मिलेगी नई गति

अहमदाबाद (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 5 जून, 2026 को गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे सूरत से भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के कुल मिलाकर 18,777 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। दक्षिण गुजरात अंचल के विकास को वेग देने वाले इन विकास कार्यों में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) अंतर्गत 1063.43 करोड़ रुपए की लागत से 8 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शामिल है। इसके तहत भरूच को 894 करोड़ रुपए से अधिक के तथा वलसाड को 169.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भेंट मिलने जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स से दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषित जल निस्तारण तथा ड्रैनेज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री भरूच में 894 करोड़ रुपए से अधिक के 6 जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। भारत के औद्योगिक विकास में गुजरात हमेशा शीर्ष पर रहा है, जिसमें भरूच जिला केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर आया है। भरूच की औद्योगिक क्षमता को अधिक सशक्त बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री 894 करोड़ रुपए से अधिक के 6 जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। दहेज पीसीपीआईआर औद्योगिक क्लस्टर में सायखा पंपिंग स्टेशन से दहेज के लैंडफॉल पॉइंट तक 90 एमएलएडी क्षमता की ऑफशोर व ऑनशोर एफ्लुएंट निस्तारण पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें 5 वर्ष के ऑपरेशन तथा मैंटेनेंस (ओ एंड एम) के साथ सिविल स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कम्पोनेंट्स और पीएलसी स्काडा सिस्टम्स का डिजाइन, इरेक्शन, टेस्टिंग तथा कमीशनिंग शामिल हैं। 474.61 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से दहेज तथा सायखा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी के निस्तारण एवं प्रबंधन को और मजबूती मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दहेज पीसीपीआईआर क्षेत्र में मुख्यतः रासायनिक, टेक्सटाइल, फार्मा, डाइज एवं इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास के लिए ढाँचागत सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। हाल में इस क्षेत्र में 1,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा; भरूच जिले के जंबूसर स्थित बल्क ड्रग पार्क में फार्मास्युकिल उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रैनज नेटवर्क तथा सेंट्रल ड्रेन जैसी महत्वपूर्ण अंतरढाँचागत सुविधाएँ विकसित की गई हैं। 274.96 करोड़ रुपए के खर्च से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट से बल्क ड्रग पार्क के ढाँचागत विकास को वेग मिलेगा। प्रधानमंत्री दहेज-2 औद्योगिक बस्ती (क्षेत्र/परिसंपदा) के लिए 30 एमएलडी ड्रैनेज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि दहेज-2 औद्योगिक बस्ती में सुवा पंपिंग स्टेशन से अंतिम पंपिंग स्टेशन जेड-93 तक राइजिंग मेन के साथ 30 एमएलडी क्षमता के ड्रैनेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट से औद्योगिक ड्रैनेज प्रबंधन अधिक कार्यक्षम बनेगा तथा एकीकृत एफ्लुएंट वहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा; पानोली विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में फ्लेक्सिबल रोड पेवमेंट, क्रॉस ड्रैनेज वर्क, जलापूर्ति नेटवर्क, कम्पाउंड वॉल, पेवर ब्लॉक, वृक्षारोपण और स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न ढाँचागत सुविधाओं का विकास किया गया है। इन विकास कार्यों से इस औद्योगिक क्षेत्र में अधिक अच्छी ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। अन्य प्रोजेक्ट्स में अंकलेश्वर में एफ्लुएंट ट्रांसमिशन पाइपलाइन पर इंटरमीडिएट बूस्टर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदूषित जल का कार्यक्षम वहन तो होगा ही, साथ ही पर्यावरणीय मानदंडों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार; दहेज-1 औद्योगिक बस्ती की वर्षा जल वहन क्षमता सुधारने, जल भराव के जोखिम कम करने तथा क्षेत्र के समग्र वर्षा जल की निकासी की व्यवस्था के ढाँचे को मजबूत करने के लिए नेचुरल ड्रेन-2 का अपग्रेडेशन किया गया है।

वलसाड में 169 करोड़ रुपए से अधिक के जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण

वलसाड जिले के सरीगाम में प्रधानमंत्री जीआईडीसी के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। इसके तहत सरीगाम स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की क्षमता 15 एमएलडी से बढ़ाकर 25 एमएलडी की गई है। इससे प्रदूषित जल के शुद्धिकरण की क्षमता में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय मानदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित होगा। इस प्रोजेक्ट में डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कन्स्ट्रक्शन, कमीशनिंग, टेस्टिंग, ट्रायल रन तथा ऑपरेशन मैंटेनेंस और रिपेयरिंग कार्य शामिल हैं। इसके अलावा; सरीगाम औद्योगिक बस्ती (क्षेत्र) में संप तथा पंपिंग स्टेशन के साथ एचडीपीई ऑनशोर व ऑफशोर आउटफॉल पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट अंतर्गत पंपिंग स्टेशन से लैंडफॉल चैम्बर तथा गहरे समुद्र में निस्तारण के स्थल तक एचडीपीई ऑनशोर व ऑफशोर पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया गया है।

डीके शिवकुमार ने ली सीएम पद की शपथ

■जी परमेश्वर उपमुख्यमंत्री बने; सिद्धारमैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली

बैंगलुरु(ईएमएस)। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार ने बुधवार को कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में लोक भवन में शपथ ली। उन्होंने अपने दादा गंगाधर के नाम पर शपथ ली। जबकि राज्य के नए डिप्टी सीएम बने जी. परमेश्वर ने डॉ. बीआर अंबेडकर के नाम पर शपथ ली। शिवकुमार के अलावा 13 विधायकों ने भी शपथ ली। इनमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। इससे पहले शिवकुमार मंच पर एक-एक नेता से मिले। उन्होंने राहुल गांधी, खरगे और अन्य नेताओं का शॉल और फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात ये रही कि पहले लोकभवन में होने वाले कार्यक्रमों का मंच पश्चिम दिशा की ओर होता था। इस बार ज्योतिषी की सलाह पर मंच पूर्व दिशा की ओर तैयार किया गया। पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने संभाली। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। वोक्कालिगा, लिंगायत और दलित कोटा के तहत तीन-तीन मंत्रियों को मंत्री पद दिए गए हैं। जबकि कुरुबा समुदाय से दो मंत्रियों को पद मिले हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम और ईसाई कोटा के तहत एक-एक मंत्री पद देकर सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। शिवकुमार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री सतीशान, हरिप्रसाद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राजीव शुक्ला, फिल्म सितारे और डीके के परिवार के सदस्य भी इस समारोह में शामिल हुए। खास बात ये है कि बीजेपी से निष्कासित विधायक शिवराम हेब्बर और एसटी सोमशेखर भी मौजूद रहे।

बढ़ते तापमान से जीव सृष्टि अलर्ट मोड पर

(विश्व पर्यावरण दिवस विशेष – 05 जून 2026)

लेखक :- डॉ. प्रितम भि. गेडाम
मोबाइल/व्हॉट्सएप्प
क्र.08237417041
ईमेल:- prit00786@gmail.com

जीव सृष्टि के लिए केवल एकमात्र आधार पेड़ है, पेड़ खत्म मतलब पृथ्वी से जीवन समाप्त। प्रकृति का एकदम सरल नियम है कि, पेड़ हमें बचाते है, हमें उन्हें बचाना हैं। अगर हम प्रकृति की रक्षा में लिए 1 प्रतिशत भी योगदान देते है तो उसके तुलना में प्रकृति 100 प्रतिशत समृद्धि हमें लौटाती हैं। कोरोना काल में हम सबने देखा की, जब प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप थम गया था, तब प्रकृति तेजी से अपनेआप को समृद्ध कर रही थी। आज विडंबना है कि, जो निस्वार्थ समृद्ध पेड़ दशकों तक माँ की तरह हमें अपने आँचल की छांव में धूप से बचाता था, फल-फूल देता था, पंछियों का रैनबसेरा हुआ करता था, बरसात में भूमि के कटाव को रोकता था, मनुष्य के लिए जहरीली कार्बनडाय ऑक्साइड को खुद अवशोषित करके प्राणवायु ऑक्सीज़न हमें देता था। वातावरण में नमी और तापमान को नियंत्रित कर प्राकृतिक स्त्रोतों को समृद्ध बनाने में मुख्य भूमिका निभाता था। आज उसी पेड़ को काटने पर लोगों को जरा भी दुःख नहीं होता, जबकि हमारे पुरे जीवन और स्वास्थ्य पर इसका गंभीर परिणाम हो रहा है, क्या हम इतने गिरे हुए स्वार्थी लोग है कि, जो हमें जीवन देगा उसकी जान हम ही लेंगे।

आज प्रकृति में बदलते वातावरण की चोट हम सबको झेलनी पड़ रही है, स्वार्थी लोगों की गलत नीतियों ने संपूर्ण पर्यावरण में जहर घोल दिया हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जंगल कटाई ने पृथ्वी पर तापमान बढ़ाया है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों में बेतहाशा वृद्धि हो रही हैं। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा, सड़के आग की भट्टी की तरह महसूस हो रही है और भूजल स्तर तेजी से गिर रहा हैं। खाद्यान्नों में लगातार बढ़ती घातक रासायनिक समृद्धता लोगों को मौत के मुंहाने पर धकेल रही हैं। एक दशक पहले तक जब धूप में घूमते थे, बच्चे धूप में खेलते थे, तो सिर्फ गर्मी महसूस होती थी, खेलते-खेलते किसी पेड़ के छांव में भी बैठ जाएं तो बड़ी ठंडक महसूस होती थी। लेकिन अब तो यह धूप जहरीली हो चुकी है, शरीर को तपाने के साथ उबालती, बीमार भी करती हैं। शहरों के कॉन्क्रीट के जंगल में घने छायादार वृक्ष का दिखना भी दुर्लभ होता जा रहा हैं।

लू से मरनेवालों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, सबसे ज़्यादा असर गरीबों, बुज़ुर्गों, बच्चों और अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों पर पड़ता है, क्योंकि जीवन यापन के लिए उनका संघर्ष अत्यधिक कष्टदायक होता हैं। सीईईडब्ल्यू के अनुसार, निर्माणकार्य मज़दूरों, गिग वर्कर्स और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों जैसे कमज़ोर तबकों को गर्मी के तनाव का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता हैं। गरीबों को इस गर्मी में भी दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहत करने पर मजबूर होना पड़ता है, उनकी आमदनी और उत्पादकता दोनों गिरती हैं। गर्मी के कारण 2030 तक जीडीपी में 4.5 प्रतिशत तक की संभावित गिरावट आ सकती है, गर्मी के कारण फसलों को नुकसान और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता हैं। 'द लैंसेट' में 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, लू के दौरान काम करने की क्षमता कम होने से हर साल लगभग 194 अरब डॉलर की आमदनी का नुकसान होता है, इस सदी के आखिर तक पूरे भारत में गर्मियों में चलने वाली लू की घटनाएं 300 से 400 फीसदी तक बढ़ सकती हैं।

गर्मियों में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिरने के कारण बहुत से ग्रामीणों और दूर-दराज क्षेत्र के रहवासियों को पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ रहा है, अनेक बार सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो वायरल होते है, जिसमे हम देखते है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक थोडेसे पानी के लिए रोजाना कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलते है, जान जोखिम में डालकर 50-60 फीट नीचे गहरे गड्ढे में उतरकर दूषित जल पिने के लिए बर्तनों में भरते हैं। जीवनावश्यक जल के लिए ऐसा संघर्ष, मजबूरी देखकर बहुत दुःख होता हैं। प्रकृति ने हर एक के लिए शुद्ध जल, हवा, पोषक खाद्य की सुविधा की है, परंतु प्रकृति का संतुलन बिगाड़कर स्वार्थी मनुष्य ने समस्त जीवसृष्टि के लिए खतरा पैदा किया हैं। लोगों के ये हाल है तो, इस बढ़ते तापमान में जंगलों में बेजुबान वन्य पशुओं के कितने बुरे हालात होते होंगे।

भौगोलिक रूप से हमारा देश उष्ण माना जाता है, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने से वातावरण में गर्मी बढ़ी है, इससे मूल तापमान लगातार बढ़ता जाता है, प्राकृतिक हरियाली और प्राकृतिक ठंडक देने वाले संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। तेज़ी से फैलते शहर प्राकृतिक नज़ारों की जगह कंक्रीट और काँच की इमारतें खड़ी हुयी, ये दिन में गर्मी सोखकर रात में धीरे-धीरे उसे बाहर निकालती हैं, जिससे सूरज डूबने के बाद भी शहरों का तापमान कम नहीं हो पाता। विकास के लिए शहरों के आसपास के सभी गांवों से उपजाऊ भूमि और खेती पर इमारतें बन रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, दुनिया भर में हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाते है, यह हर 12 महीने में आइसलैंड या पुर्तगाल के बराबर एरिया को साफ़ करने के बराबर हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, भारत में हर साल खेती, वनों की कटाई और बुनियादी ढांचे का विकास की वजह से 1,00,000 हेक्टेयर से ज़्यादा प्राकृतिक जंगल और वृक्ष आवरण खत्म हो जाता हैं। मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार, विकास प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार की इजाज़त से हर साल लगभग 20 से 30 लाख पेड़ काटे जाते हैं।

1990 और 2000 के बीच भारत में 384,000 हेक्टेयर जंगल कम हुए, लेकिन 2015 और 2020 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 668,400 हेक्टेयर हो गया। यूनाइटेड किंगडम की एक वेबसाइट, यूटिलिटी बिडर, जो एनर्जी और यूटिलिटी कॉस्ट की तुलना करती है, की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पर है, जहाँ इन सालों में औसतन 668,400 हेक्टेयर जंगल काटे गए। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जहाँ ब्राज़ील ने 2015 और 2020 के बीच 2,559,100 हेक्टेयर और इंडोनेशिया ने इसी समय में 1,876,000 हेक्टेयर जंगल काटे, वहीं भारत के आंकड़े काफी बढ़ गए है, 'डाउन टू अर्थ' ने भी यह खबर प्रकाशित की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और डीम्ड यूनिवर्सिटी सस्त्रा के अनुसंधानकर्ताओं की एक नये अध्ययन से पता चला है कि 2015 और 2019 के बीच भारत के जंगल वनक्षेत्र में काफ़ी गिरावट आयी हैं। इन वर्षों में भारत में 18 वर्ग किलोमीटर जंगल वनक्षेत्र खत्म हुआ, जबकि इसके मुकाबले केवल 1 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। यह बेहद चिंताजनक रेश्यो है जो भारत के वन पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर 'विखंडन संकट' को दिखाता हैं। जबकि भारत सरकार के प्रमुख नोडल एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार, भारत नेट सालाना वन क्षेत्र लाभ के मामले में दुनिया भर में तीसरा स्थान बनाए हुए है। वन हानि की वार्षिक दर 10.7 मिलियन हेक्टेयर (1990झ्र2000) से गिरकर 4.12 मिलियन हेक्टेयर (2015-2025) हो गई।

हमसे अच्छे तो जंगली जीव है, जो अपने प्राकृतिक अधिवास को बचाने और उन्हें समृद्ध बनाने में प्रकृति की सही मायने में रक्षा करते हैं। पेड़ों से जंगल समृद्ध होते है, जंगल से शुद्ध पानी के स्त्रोत समृद्ध, शुद्ध प्राणवायु समृद्ध, तापमान नियत्रण, जंगल में वन्यजीव समृद्ध, जीवों में खाद्यश्रृंखला सुचारु रूप में चलती है, वन्यजीवों और मानवीय संघर्ष में कमी होती है, प्रदुषण में कमी आती है, बीमारियां कम होकर मानवीय स्वास्थ्य मजबूत होता हैं। ऋतुओं का चक्र तय समय पर ठीक ढंग से कार्यान्वित होता है, फसलें लहलहाती है, प्राकृतिक आपदाओं में कमी आती है, प्रत्येक नागरिक तक खाद्य सुरक्षा की नींव मजबूत बनाने में सहयोग मिलता हैं। मानवीय जरूरतों की योग्य मात्रा में पूर्ति होती है, अमीरी-गरीबी के बीच की खाई पाटने में मदद मिलती हैं। महंगाई नियंत्रण में लाने में सहायता मिलती है और तब देश खुशहाल और सही मायने में विकसित होता हैं।

कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला, भारतीय नागरिक की मौत; 63 घायल

नई दिल्ली (ईएमएस)। कुवैत में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए कथित ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमले में घायल हुए लोगों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए तत्काल 25 एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गईं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ड्रोन हमले से एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति का जायजा लेने के बाद एहतियातन कुछ समय के लिए एयरपोर्ट का संचालन और हवाई यातायात रोक दिया। इससे यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान ने कुवैत में तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर कई ड्रोन हमले किए थे, हालांकि उन सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया था। ताजा घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं।

इस्कॉन ब्रिज हिट एंड रन केस: मुख्य आरोपी तथ्य पटेल को मिली जमानत, करीब 34 महीने बाद जेल से रिहाई

■ सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दी; एक करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पूरी होने के बाद साबरमती सेंट्रल जेल से रिहा हुआ आरोपी

अहमदाबाद (ईएमएस)। शहर के इतिहास के सबसे भयावह और चर्चित इस्कॉन ब्रिज जगुआर हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी तथ्य पटेल को आखिरकार लंबी अवधि के बाद जेल से रिहाई मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित जमानत मंजूर किए जाने के बाद बुधवार को सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर उसे साबरमती सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जुलाई 2023 की उस काली रात के बाद से तथ्य पटेल लगातार जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति अहमदाबाद की निचली अदालत और जेल प्रशासन को प्राप्त होने के बाद उसकी रिहाई की औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। जेल से बाहर आते समय तथ्य पटेल के पिता प्रज्ञेश पटेल स्वयं उसे लेने साबरमती सेंट्रल जेल पहुंचे थे। सभी आवश्यक दस्तावेजों और कानूनी औपचारिकताओं की जांच पूरी होने के बाद वे अपने बेटे को साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। गौरतलब है कि इस हादसे के बाद पूरे गुजरात में तथ्य पटेल और उसके पिता के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिला था। यह मामला सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर राज्यभर में चर्चा का केंद्र बन गया था।

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

स्थानीय अदालत और गुजरात हाईकोर्ट से कई बार जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए लंबे समय को ध्यान में रखते हुए उसे नियमित जमानत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने जमानत देते हुए एक कड़ी शर्त भी लगाई है। इसके तहत तत्य पटेल को अदालत में 1 करोड़ रुपये की राशि जमा करानी होगी। इस शर्त और अन्य कानूनी नियमों का पालन किए जाने के बाद ही जेल प्रशासन ने उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। तथ्य पटेल लगभग 2 वर्ष 10 महीने यानी करीब 34 महीने तक जेल में बंद रहा।

UT ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU

Land Section Collectorate, Diu

Public Hearing Notice in respect of draft Rehabilitation and Resettlement Scheme as per Section 16 of the RFCTLARR Act, 2013

Purpose: For the project of "Development of infrastructure facilities-hospitality, recreation, leisure, exhibition, etc. to the visiting tourists in Diu District.

Public Hearing Notice No. 65-02(Part)-LAQ-2024-25/612 dated 01/06/2026

Note: Details can be downloaded from https://tinyurl.com/56h89ued or by scanning the QR code.

Office of the Collector, Diu

IP/DMN/2/5/2026-27-219 DTD:-03/06/2026

CHANGE OF NAME

I HAVE CHANGED MY NAME FROM JESHALBEN PRADEEPKUMAR PUNAMIYA TO **JESHAL UPSHAM SHAH** AS PER DOCUMENT.
ADDRESS :1051-1, BUNGLOW NO.2,B/H WOODLAND IN,TOKARKHADA,SILVASSA - 396230

संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव एवं नई दिल्ली

असली आज़ादी

गुरुवार 04, जून 2026, दमण।

पीएम मोदी के दौरे को लेकर रिंगणवाडा ग्राम पंचायत में जनसभा एवं स्वच्छता अभियान के साथ नागरिकों को दिया गया आमंत्रण

■ रिंगणवाडा ग्राम पंचायत सरपंच चैताली कामली, जिला पंचायत सदस्य ईश्वर पटेल, पंचायत सदस्यों एवं नागरिकों ने ग्रामीणों को दिया आमंत्रण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। पीएम मोदी के 5 जून को प्रस्तावित दमण दौरे को लेकर रिंगणवाडा ग्राम पंचायत में जनसभा, स्वच्छता अभियान के साथ-साथ नागरिकों को आमंत्रण देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके तहत रिंगणवाड़ा पंचायत ने निवासियों के लिए स्वच्छता, सफाई और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न इलाकों में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। रिंगणवाडा ग्राम पंचायत सरपंच चैताली कामली, जिला पंचायत सदस्य ईश्वर पटेल उप सरपंच जयेश कामली पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और स्थानीय स्वयंसेवकों ने इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया और सार्वजनिक स्थानों, सड़कों तथा सामुदायिक क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित की। स्वच्छता अभियान के अलावा, पंचायत अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के दौरे की सूक्ष्म-योजना पर चर्चा करने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ बैठकें की। इन बैठकों ने नागरिकों को दौरे के संबंध में अपनी चिंताओं, सुझावों और अपेक्षाओं को साझा करने का अवसर प्रदान किया। निवासियों के साथ बातचीत के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के आगामी दौरे के बारे में भी जागरूकता फैलाई गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने रिंगणवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने और इसकी सफलता में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। नागरिकों को बड़ी संख्या में शामिल होने और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पंचायत ने स्वच्छता बनाए रखने, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और क्षेत्र की प्रगति तथा विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही पहलों का समर्थन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डाभेल पंचायत टीम ने ग्रामीणों को दिया आमंत्रण

■ डाभेल ग्राम पंचायत सरपंच हेमाक्षी पटेल एवं जिला पंचायत सदस्य तोरल पटेल ने पंचायत टीम के साथ घर-घर जाकर नागरिकों को दिया आमंत्रण पत्रिका, चलाया सफाई अभियान

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमण आगमन के उपलक्ष्य में डाभेल ग्राम पंचायत द्वारा जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डाभेल ग्राम पंचायत की सरपंच हेमाक्षी पटेल, जिला पंचायत सदस्य तोरल पटेल, ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा बड़ी संख्या में ग्रामजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान घर-घर जाकर ग्रामजनों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में बही संख्या में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्रिका वितरित की गई। साथ ही दमण में हुए सर्वांगीण विकास कार्यों तथा विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं चित्र ग्रामजनों के समक्ष प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर ग्रामजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। उपस्थित ग्रामजनों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में सहभागी बनकर उसे सफल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके साथ ही सफाई अभियान भी चलाया गया।

पीएम मोदी के 5 जून को दमण दौरे को लेकर कडैया ग्राम पंचायत ने चलाया विशेष जनसंपर्क अभियान, नागरिकों को दिया आमंत्रण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 03 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जून को दमण दौरे को लेकर कडैया ग्राम पंचायत द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कडैया सरपंच शंकर पटेल, जिला पंचायत सदस्य हर्षल पटेल एवं पंचायत सदस्यों ने पंचायत क्षेत्र के घरों में जाकर नागरिकों को पीएम मोदी के कार्यक्रम में बडी संख्या में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे इसके लिए सफाई अभियान भी चलाया गया। इस दौरान पंचायत विस्तार में साफ-सफाई करके स्वच्छ एवं सुंदर गांव का संदेश दिया गया।

दमण जिला प्रशासन ने 5 जून को वीवीआईपी विजिट को लेकर जारी किये रूट मैप

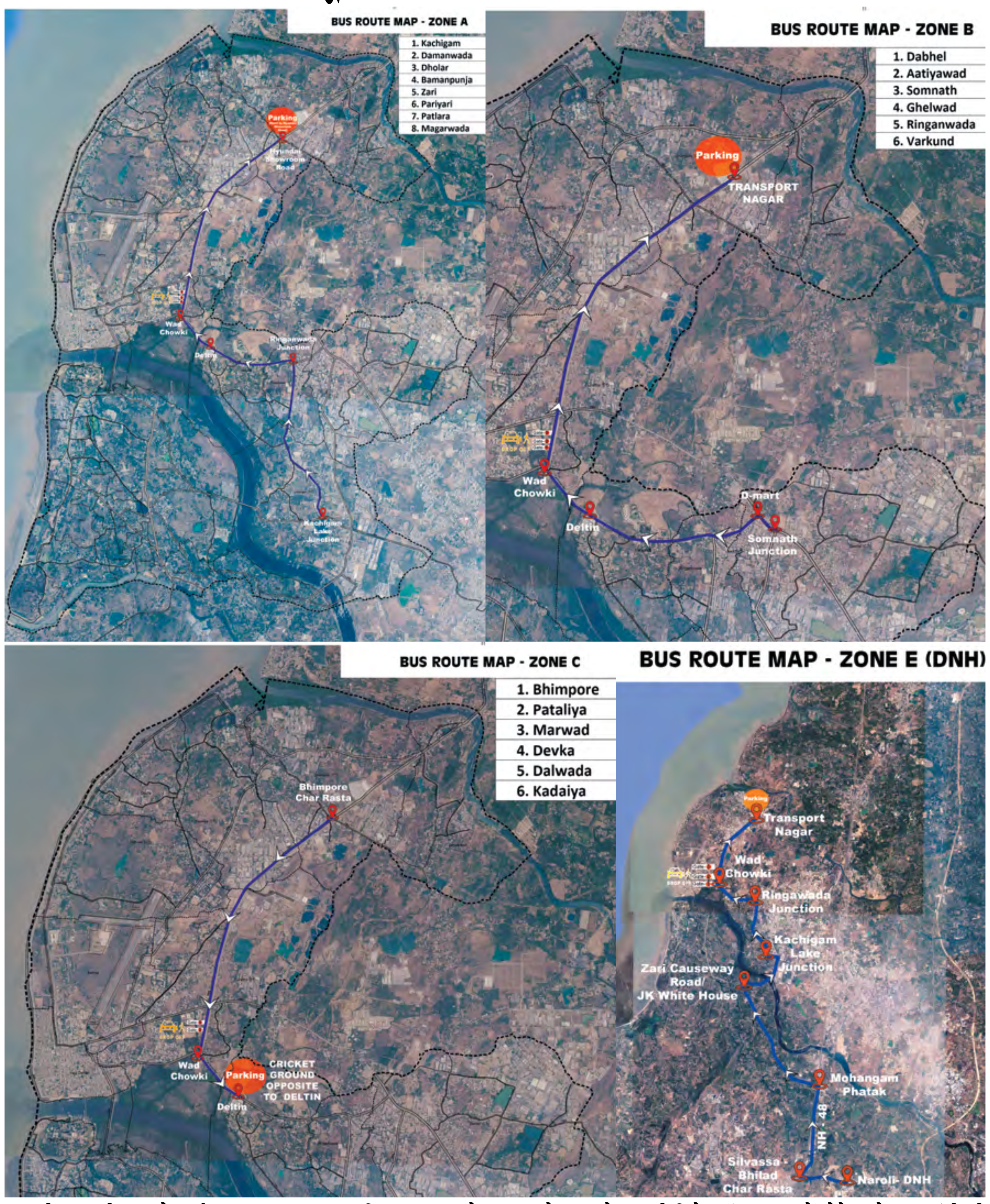

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 3 जून। दमण जिला प्रशासन ने 5 जून को दमण के स्वामी विवेकानंद ग्राउन्ड में होने वाले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए नागरिकों को सुविधा रहे इसके लिए आज ट्रैफिक रूट और पार्किंग स्थलों को लेकर रूट मैप जारी किया है। जिला प्रसाशन ने नागरिकों से निवेदन किया है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाये गये जोन में तय की गई पंचायतों को उसी रूट का कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैप में दिखाये गये पार्किंग स्थल का ही पार्किंग के लिए उपयोग करना है।

पीएम मोदी के 5 जून को प्रस्तावित दमण दौरे को लेकर दुनेठा ग्राम पंचायत की टीम ने घर-घर जाकर नागरिकों को दिया आमंत्रण

■ दुनेठा ग्राम पंचायत सरपंच आशा पटेल, उप सरपंच रमेश भंडारी, पंचायत सदस्य एडवोकेट संजय पटेल, युवा भाजपा अग्रणी संजय पटेल सहित की टीम ने जानू की वाडी क्षेत्र में जनसंवाद के साथ दिया निमंत्रण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। 5 जून को पीएम मोदी की होने वाली दमण यात्रा को लेकर दुनेठा ग्राम पंचायत की टीम ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को आमंत्रण दिया। दुनेठा ग्राम पंचायत सरपंच आशा पटेल, उप सरपंच रमेश भंडारी, पंचायत सदस्य एडवोकेट संजय पटेल, युवा भाजपा अग्रणी संजय पटेल सहित की टीम ने जानू की वाडी क्षेत्र में जनसंवाद के साथ निमंत्रण दिया। सरपंच आशा पटेल और संजय पटेल ने नागरिकों से कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी दमण को एयरपोर्ट, अस्पताल, कॉलेज सहित अनेक भेंट देने आ रहे हैं। हम सभी को इस अवसर पर उपस्थित रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत करना है।

पीएम मोदी के दमण आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा की टीम ने जनसंवाद कर जनता को दिया आमंत्रण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 03 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जून को दमण दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा की टीम ने दमण जिले के विभिन्न विस्तारों में नागरिकों के साथ जनसंवाद कर आमंत्रण दिया। इस दौरान प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा अध्यक्ष वीरेश भक्ति, महामंत्री मिलन माह्यावंशी, एससी मोर्चा दमण जिला अध्यक्ष महेश वांकडकर, राज पटेल, केवल खारवा, हिरेन दमणिया, परेश दमणिया, सचिन पटेल, रितेश दमणिया, कांतिभाई दमणिया सहित ने विभिन्न पंचायत क्षेत्र में जाकर 5 जून को दमण में स्वामी विवेकानंद ग्राउंड पर पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रम में बडी संख्या में शामिल होने के लिए नागरिकों को आमंत्रण दिया। नागरिकों ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में उपस्थित रहने के लिए उत्साह दिखाया।

डीएमसी काउंसिलर जयंती पटेल ने पीएम मोदी के दमण दौरे को लेकर चलाया स्वच्छता अभियान

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 03 जून। 5 जून को पीएम मोदी के होने वाले दमण दौरे को लेकर शहरी विस्तार में साफ-सफाई सहित अन्य तैयारियां जोरों से चल रही है। इसी के तहत डीएमसी वॉर्ड नं.12 के काउंसिलर जयंती पटेल ने अपनी टीम के साथ अपने वॉर्ड विस्तार में स्वच्छता अभियान चलाया। इसके साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम में बडी संख्या में शामिल होने के लिए वॉर्डवासियों को आमंत्रण भी दिया।

दो टूक- टूटते भरोसे के वेंटिलेटर पर देश की परीक्षा व्यवस्था

योगेश कुमार गोयल

सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति। जब तक सरकार इस समस्या को 'राष्ट्रीय आपदा' की तरह नहीं देखेगी, तब तक आधे-अधूरे समाधान ही सामने आएंगे। नीट-यूजी 2026, सीबीएसई ओएसएम विवाद और एससएससी परीक्षा धांधली, ये घटनाएं चेतावनी हैं। यदि अब भी कठोर और स्थायी सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में हर परीक्षा संदेह के घेरे में होगी। तब सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि पेपर लीक हुआ बल्कि यह होगी कि देश के युवाओं का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा।

भारत में परीक्षा अब केवल योग्यता का आकलन नहीं रह गई है बल्कि यह करोड़ों सपनों की निर्णायक कसौटी बन चुकी है लेकिन जब यही कसौटी बार-बार संदिग्ध हो जाए, जब मेहनत और ईमानदारी की जगह 'जुगाड़' और 'माफिया नेटवर्क' हावी हो जाएं, तब यह केवल परीक्षा का संकट नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य का संकट बन जाता है। पेपर लीक के चलते नीट-यूजी 2026 परीक्षा का रद्द होना, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल और एसएससी जीडी परीक्षा में धांधली, ये घटनाएं मिलकर यह साबित करती हैं कि भारत की परीक्षा प्रणाली अब गहरे संस्थागत संकट में फंस चुकी है और भारत की परीक्षा प्रणाली अब वेंटिलेटर पर है। नीट-यूजी 2026 का घटनाक्रम तो इस विफलता की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। लगभग 22.79 लाख छात्रों की मेहनत, उनके परिवारों के त्याग और वर्षों की तैयारी एक झटके में शून्य हो गई। यह केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं था बल्कि उस विश्वास का टूटना था, जिस पर पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार मामला केवल बाहरी गिरोहों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जांच में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के भीतर तक मिलीभगत के आरोप सामने आए। सीबीआई की जांच और संसदीय समिति की पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर चुनिंदा छात्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने का काम किया। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत विश्वासघात है। जिस संस्था को निष्पक्षता की गारंटी देनी थी, वही यदि धांधली का हिस्सा बन जाए तो पूरी व्यवस्था का नैतिक आधार ही खत्म हो जाता है। नीट पेपर लीक की प्रकृति भी सामान्य नहीं थी। 'गेस पेपर' के नाम पर लगभग 150 से अधिक प्रश्नों का हूबहू मिल जाना, परीक्षा से पहले 600 अंकों तक के सवालों का प्रसार, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम प्रश्नपत्र का घूमना, ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकते। यह एक संगठित, बहुस्तरीय और तकनीकी रूप से सक्षम नेटवर्क का संकेत है, जो परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी को भेद चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में पेपर लीक के बाद भी कोई ठोस सुधार क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, जांच समितियों और सिफारिशों के बावजूद 2026 में स्थिति और बदतर कैसे हो गई? इसका सीधा अर्थ है कि समस्या तकनीकी कम और इच्छाशक्ति की अधिक है।

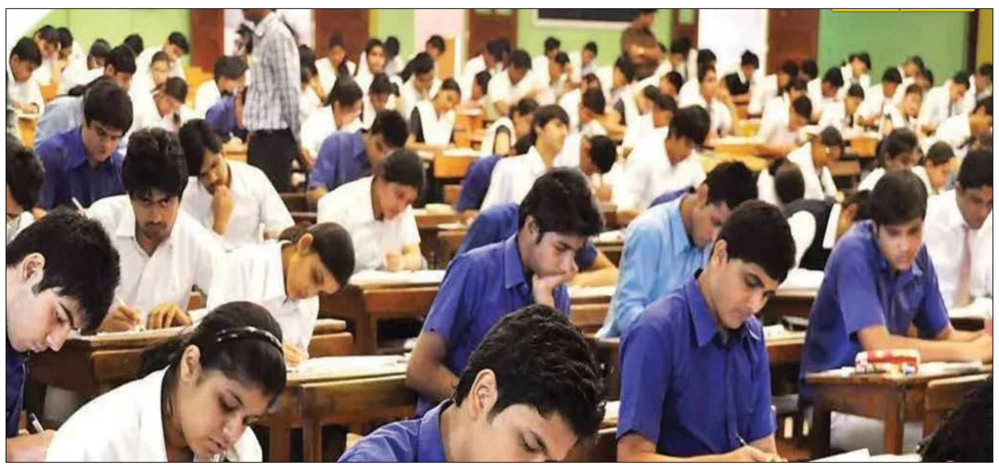

भारत की परीक्षा प्रणाली का ढ़ांचा ही कई स्तरों पर कमजोर है। प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में निजी एजेंसियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहती है। यही वह जगह है, जहां से माफिया नेटवर्क अपनी जड़ें जमाता है। जब प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही स्कैन होकर डिजिटल रूप में फैल सकता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि सुरक्षा तंत्र केवल कागजों पर मजबूत है, जमीन पर नहीं। दूसरी ओर, कोचिंग उद्योग का अनियंत्रित विस्तार इस संकट को और गहरा कर रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं अब हजारों करोड़ रुपये का बाजार बन चुकी हैं। इस बाजार में 'सफलता' एक उत्पाद है, जिसे खरीदने के लिए छात्र और अभिभावक किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। इसी मानसिकता का फायदा उठाकर एजुकेशन माफिया 'सीक्रेट पेपर', '100 प्रतिशत सलेक्शन गारंटी' और ह्यइनसाइडर एक्सेसह्ण जैसे झूठे वादों के जरिए पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है।

यदि नीट प्रकरण परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है तो सीबीएसई का ओएसएम विवाद मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर चोट करता है। डिजिटल मूल्यांकन को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था लेकिन इसके परिणाम उलटे दिखाई दिए। पास प्रतिशत में गिरावट, मेधावी छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिलना और स्कैन की गई कॉपियों में भारी गड़बड़ियां, ये सब इस बात के संकेत हैं कि तकनीक को बिना पर्याप्त तैयारी और परीक्षण के लागू किया गया। कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी कॉपियां धुंधली थी, कुछ को गलत उत्तर पुस्तिकाएं मिली और कुछ मामलों में तो पूरी कॉपी ही किसी और की थी। यह स्थिति केवल तकनीकी त्रुटि नहीं मानी जा सकती बल्कि यह सरासर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। यदि एक छात्र की मेहनत को किसी दूसरे की कॉपी से बदल दिया जाए तो यह केवल गलती नहीं है बल्कि उस छात्र के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड भले ही इन खामियों को सीमित मामलों तक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करें लेकिन छात्रों में बढ़ता असंतोष इस बात का प्रमाण है कि समस्या व्यापक है।

तीसरी बड़ी घटना, एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में धांधली, इस बात को और स्पष्ट करती है कि यह संकट किसी एक परीक्षा या संस्था तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पेपर लीक, तकनीकी खराबी और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ द्वारा पकड़े गए रैकेट ने इस धांधली के आधुनिक रूप को उजागर किया। प्रॉक्सी सर्वर, स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स और डमी कैंडिडेट्स के जरिए परीक्षा में हेरफेर किया जा रहा था। यह पारंपरिक नकल या पेपर लीक से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी प्रणाली को भीतर से हैक किया जा रहा है। इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एक भयावह तस्वीर उभरती है, एक ऐसी व्यवस्था, जहां प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं, मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सबसे अधिक पीड़ित वह छात्र है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र, जिनके माता-पिता ने कर्ज लेकर या जमीन गिरवी रखकर उन्हें कोचिंग दिलाई, आज सबसे ज्यादा निराश हैं। एक परीक्षा रद्द होने का मतलब केवल दोबारा परीक्षा देना नहीं होता बल्कि यह मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और आत्मविश्वास के टूटने का कारण बनता है।

इस पूरे संकट का एक और खतरनाक पहलू है व्यवस्था के प्रति बढ़ता अविश्वास। जब छात्र यह मानने लगें कि सफलता मेहनत से नहीं बल्कि 'सेटिंग' से मिलती है तो यह केवल शिक्षा का नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी पतन है। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? क्या हर बार जांच, गिरफ्तारी और बयानबाजी से काम चल जाएगा? स्पष्ट है कि नहीं। सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में पूर्ण डिजिटल और एन्क्रिप्टेड मॉडल लागू करना होगा। प्रश्नपत्रों को परीक्षा से कुछ मिनट पहले तक सुरक्षित सर्वर में रखा जाए और सीधे केंद्रों पर डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाए। इससे छपाई और परिवहन से जुड़ी कमजोरियां समाप्त होंगी। दूसरा, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को सीमित करना होगा। संवेदनशील कार्यों में केवल प्रशिक्षित और जवाबदेह सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा, पेपर लीक को संगठित आर्थिक अपराध घोषित कर इसके लिए गैर-जमानती कठोर कानून बनाए जाएं। जब तक अपराधियों को कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह धंधा बंद नहीं होगा। चौथा, साइबर निगरानी को मजबूत करना होगा। टेलीग्राम, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए विशेष एजेंसियां बनाई जानी चाहिए। पांचवां, तकनीक को लागू करने से पहले उसका व्यापक परीक्षण और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। सीबीएसई ओएसएम विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना तैयारी के लागू की गई तकनीक समाधान नहीं बल्कि नई समस्या बन सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति। जब तक सरकार इस समस्या को 'राष्ट्रीय आपदा' की तरह नहीं देखेगी, तब तक आधे-अधूरे समाधान ही सामने आएंगे। नीट-यूजी 2026, सीबीएसई ओएसएम विवाद और एसएससी परीक्षा धांधली, ये घटनाएं चेतावनी हैं। यदि अब भी कठोर और स्थायी सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में हर परीक्षा संदेह के घेरे में होगी। तब सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि पेपर लीक हुआ बल्कि यह होगी कि देश के युवाओं का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। और जिस राष्ट्र के युवा ही अपनी व्यवस्था पर विश्वास खो दें, उसके भविष्य की नींव कितनी कमजोर हो जाती है, यह समझना मुश्किल नहीं है।

संपादकीय

नशे पर शिकंजा

निस्संदेह, नशे का निरंतर फैलता काला कारोबार एक राष्ट्रीय संकट है। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के विदेशों से आने वाले नशीले पदार्थों की बरामदगी भयावह संकट की तसवीर उकेरती है। संगठित विदेशी अपराधियों की साजिशों और देश में फैले नशा तस्करों का गठजोड़, इस नशीले जहर के कारोबार को चला रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम खुफिया एजेंसियां व राज्य के विशेष पुलिस बल योजनाबद्ध ढंग से नशा कारोबारियों की कमर तोड़ें। लेकिन फिर भी कई राज्यों द्वारा चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान बिगड़ते हालात सुधारने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया। अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वर्षों से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है। नशे के नश्तर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सौ दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इस अभियान का सुखद पहलू यह है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, इस कोशिश को प्रतिबंधित संगठन जमाते-ए-इस्लामी के एक गुट का भी समर्थन मिला है। कहना कठिन है कि इस समर्थन का हकीकत में असर कितना होगा। लेकिन इस घोषणा ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही इस भयावह होते संकट का मुकाबला किया जा सकता है। सही मायने में समाज में व्याप्त तमाम वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सामूहिक व निरंतर प्रयासों से ही नशा मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। वास्तव में नशा विरोधी अभियान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली जटिलताओं के मुकाबले के लिये कुछ दिन, कुछ माह के अभियान के बजाय साल में 365 दिन चलने वाली रणनीति अपनाने की जरूरत है। कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियान इसके लक्ष्य को पाने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। इस संकट के समाधान के लिये नशे की लत के सामाजिक पहलुओं की भी व्यापक पड़ताल जरूरी है। कारगर समाधान हेतु सामाजिक स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत होती है। निस्संदेह, नशे की लत के तमाम कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं। जिनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। मसलन इस व्यसन के मूल में समाज में व्याप्त बेरोजगारी, निराशा, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, बुरी संगत का असर तथा मादक पदार्थों की समाज में आसान उपलब्धता आदि कारक निहित हैं। चिंताजनक है कि नशा अब स्कूल-कालेजों तक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कई राज्यों में नशे की आपूर्ति में बच्चों को इस्तेमाल करने के चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं। वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों में शिथिलता अपनायी जाती है तो सख्ती से हासिल होने वाली उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। यह सत्य है कि नशा एक ऐसा रोग है, जिसका कोई आसान इलाज उपलब्ध नहीं है। जहां एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसकी तलब को काबू करने के लिये भी प्रयास जरूरी हैं।

चिंतन-मनन

भलाई का भाव होता है यज्ञ

एक भाव होता है मेरा दूसरा है मेरे लिए और तीसरा है सबके लिए। मेरा में इंसान केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है और ये पक्का कर लेता है कि मेरे पास जो है, वो केवल मेरा है, मैंने कमाया है, मुझे मिला है और इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। यह सोच अज्ञानी लोगों की होती है, जो हमारे अहंकार को बनाये रखती है। मेरे लिए अर्थात इंसान सोचता है कि जो भी मेरे पास है, ये मेरा नहीं बल्कि मेरे लिए है। इसका स्वामी मैं नहीं बल्कि ये सब मुझे इस्तेमाल करने के लिए मिला है। वो इसी भाव को मन में रखता है। यह सोच मध्यम दर्जे के लोगों की होती हैं।

तीसरा भाव है सबके लिए मतलब जो मेरे पास है, वो मेरा ही नहीं और मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। यह विचार उत्तम दर्जे के इंसानों का होता हैं। इसी को यज्ञ कहा जाता है। जब मन में सबकी भलाई का भाव हो वही यज्ञ है। जो सबका ध्यान रखकर बाद में अपना सोचता है वही श्रेष्ठ इंसान है। इस तरह का यज्ञ अहंकार को गला देता है। ऐसी भावना के साथ साधना करने वाला ब्रह्म को पा लेता है। जो मनुष्य केवल मेरा-मेरा में ही फंसा रहता है, वो ना तो इस जन्म में सुख पाता न ही मरने के बाद परलोक में।

डिजिटल आक्रामकता के जाल में फंसा बचपन

दिलीप कुमार पाठक

आजकल घरों में शाम के वक्त एक खामोश नजारा दिखाई देता है। पूरा परिवार एक ही कमरे में, एक ही सोफे पर साथ बैठा होता है, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होती। सब के सब चुपचाप अपने-अपने मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। माता-पिता भी इस बात से बड़े खुश और बेफिक्र रहते हैं कि उनका बच्चा बाहर धूप या धूल-मिट्टी में नहीं घूम रहा है, बल्कि घर के अंदर आराम से सुरक्षित बैठा है। लेकिन क्या कभी हमने ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचने की कोशिश की है कि स्क्रीन में अपनी आंखें गड़ाए बैठा हमारा यह मासूम बच्चा अंदर ही अंदर किस मानसिक दौर से गुजर रहा है? कहीं उसके नन्हें दिमाग पर नकारात्मक असर तो नहीं हो रहा?

हर साल 4 जून को पूरी दुनिया में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पुराने जमाने में जब इस दिन की चर्चा होती थी, तो बच्चों पर अत्याचार का सीधा सा मतलब लड़ाई-झगड़े, युद्ध, दंगे या फिर फैक्ट्रियों में होने वाली बाल-मजूदरी से लगाया जाता था। लेकिन आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में मासूमों के खिलाफ होने वाली हिंसा का पूरा चेहरा ही बदल चुका है। अब यह आक्रामकता सड़क पर शोर नहीं मचाती। अब यह हिंसा बिना किसी आवाज के, इंटरनेट के महीन रास्तों से रेंगती हुई सीधे हमारे घरों के भीतर और हमारे बच्चों के दिमाग पर सीधा हमला कर रही है। जरा रुककर गंभीरता से सोचिए। आपका बच्चा आपके ठीक सामने बैठा हो सकता है, लेकिन मुमकिन है कि ठीक उसी वक्त उसका कोमल मन किसी बहुत गहरे तनाव या डर में डूब रहा हो। ऑनलाइन गेम खेलते समय किसी अनजान शख्स द्वारा दी गई गंदी गालियां, सोशल मीडिया पर दोस्तों द्वारा उड़ाया गया उसका कोई भद्दा मजाक, या फिर इंटरनेट के समंदर में छिपे किसी अपराधी की गंदी नजर। यह डिजिटल आक्रामकता ऐसी होती है जो बाहर से शरीर पर दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके जख्म और भी ज्यादा गहरे होते हैं। यह अदृश्य हमला बच्चे के आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। सबसे ज्यादा डरावना तो यह है कि इंटरनेट के इस गंदे खेल में कोई तीसरा देखने वाला गवाह नहीं होता, सिवाय उस एक सहमे हुए और अकेले पड़ चुके बच्चे के।

वैश्विक संस्था यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर तीसरा इंसान असल में एक बच्चा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी ऑनलाइन किसी न किसी रूप में मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना का शिकार होती है। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में बच्चों को रोने से रोकने या उन्हें शांत बैठाने के लिए खिलौने की जगह मोबाइल थमा देते हैं। यह डिजिटल झुनझुना शुरू-शुरू में तो हमें बड़ी राहत देता है, लेकिन धीरे-धीरे यही मोबाइल बच्चे और माता-पिता के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देता है। जब बच्चा इंटरनेट की किसी बड़ी मुसीबत या ब्लैकमेलिंग में फंसता है, तो वह लोक-लाज और डर के मारे अपने मम्मी-पापा को कुछ नहीं बता पाता। वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेता है। अब वह समय आ गया है जब हमें इस बढ़ते हुए खतरे को गहराई से समझना होगा। यह कोई ऐसी सामाजिक समस्या नहीं है जो केवल पुलिस की मुस्तैदी या सरकार के कड़े कानून बना देने भर से ठीक हो जाएगी। इस बीमारी के इलाज की शुरूआत हमारे अपने घर के भीतर से ही होगी। बच्चों को महंगे स्मार्टफोन या गैजेट्स लाकर देने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें अपना कीमती वक्त देना। अपने बच्चों के बदलते हुए बर्ताव पर हमेशा नजर रखिए। अगर आपका हंसता-खेलता बच्चा अचानक गुमसुम रहने लगा है, बात-बात पर गुस्सा कर रहा है या आपसे अपना फोन छिपाने लगा है, तो उसे डांटने या मारने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। उसके पास बैठिए, प्यार से हाथ थामिए, उससे खुलकर बातें कीजिए और उसे यह भरोसा दिलाइए कि दुनिया की चाहे जो भी मुसीबत हो, उसके मम्मी-पापा हमेशा उसके साथ खड़े हैं। इस देश के बचपन को सुरक्षित और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए, इस डिजिटल दौर में अपने बच्चों के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त बनें। उनके हाथ से कुछ देर के लिए फोन छीनकर उन्हें पास के मैदान में खेलने के लिए भेजें, रात को सोने से पहले उनसे गप्पें मारें और उन्हें खुलकर हंसने का असली मौका दें। जब तक हम उनके लिए घर में एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल नहीं बनाएंगे, तब तक स्क्रीन के पीछे का यह रोना कभी बंद नहीं होगा। हमारे देश का उज्ज्वल भविष्य मोबाइल की इस छोटी सी स्क्रीन में घुट-घुट कर जीने के लिए नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे खुलकर जिंदगी जीने के लिए है।

कमजोर मानसून तो महंगाई का लगेगा तड़का, अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित

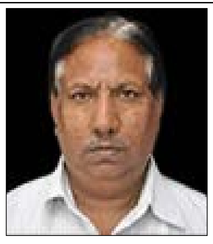

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंताजनक का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी और अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में कुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पश्चिमी भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से बिलंबित हो रहा है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक ही रही है। कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निश्चित रुप से सिंचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो कुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता।

दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे। हांलाकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं। कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की किस्में विकसित करने में हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पायें हैं। पांच नदियों के प्रदेश पंजाब तक में पानी का संकट होने लगा है। खेती ही नहीं घरेलू जरुरतों में भी पानी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। टायलेट और कूलरों में पानी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। जल बचाओ मात्र स्लोगन ही रह गया है और इसका असर दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार तो बहुत किये गये हैं पर उनके निर्माण में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है वह किसी से छिपी नहीं हैं। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितना सफल रहा है वह सामने हैं। बाहरमासी नदी नालें तो अब कल्पना की बात हो गए हैं बल्कि बरसाती नदियां भी बरसात में एकाध बार ही पूरे वेग से बहती दिखती है। ऐसे में गंभीरता को तो समझा ही जा सकता है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि मानसून हमेशा सामान्य ही रहेगा यह सोचना अपने आप में गलत होगा। जिस तरह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जंगल घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं वह किसी और की देन नहीं हमारे कारण ही हो रहा है। हालात यह हो गए हैं कि सर्दी में सर्दी नहीं और गर्मी में गर्मी को तरसने लगे हैं। यहां तक कि इस बार तो बसंत की प्रतीक्षा ही करते रह गए हैं। जनवरी फरवरी में सर्दी तो फिर मार्च अप्रेल में गर्मी का असर देखा गया। बसंत कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कहने का अर्थ है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम सामने हैं। प्राकृतिक विपदाएं अधिक होने लगी है। ग्लेसियरों में तेजी से बर्फ पिघल रही है, समयपर बर्फवारी कम होने लगी है। बेमौसम आंधी ओलावृष्टि आम होती जा रही है। खैर यह विषयांतर होगा पर कहीं ना कहीं मानसून को लेकर दीर्घकालीन रणनीति बनानी ही होगी ताकि कमजोर मानसून का जनजीवन और अर्थ व्यवस्था पर व्यापक असर नहीं पड़े। सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

असली आज़ादी

गुरुवार 04, जून 2026, दमण।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव, कथित अवैध नागरिकों को लेकर बीएसएफ और बीजीबी आमने-सामने

ढाका (एजेंसी)। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक असामान्य स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच कई दौर की बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल सीमा क्षेत्र में कुछ लोगों को लेकर दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी 24 परगना जिले के पेट्रापोल क्षेत्र स्थित जयंतिपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास कुछ कथित बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा के निकट नो-मैन्स लैंड क्षेत्र में देखा गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए। इसके बाद बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी बीजीबी ने मामले पर आपत्ति जाहिर की और संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता तथा पहचान के सत्यापन की मांग की। बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई। हालांकि प्रारंभिक बातचीत में कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल सका और मामला कुछ समय तक लंबित रहा। बीजीबी अधिकारियों का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहले उसकी नागरिकता, पते और अन्य दस्तावेजों का उचित सत्यापन आवश्यक है। मामले के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई। बीजीबी ने अपनी ओर निगरानी तेज कर दी, जबकि बीएसएफ ने भी सीमावर्ती इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाई। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों पक्षों ने सीमा पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। यह घटनाक्रम तब आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवासन, सीमा प्रबंधन और नागरिकता सत्यापन जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को वापस भेजने या स्वीकार करने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत ही पूरी की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा से जुड़े इसतरह के मामलों में दोनों देशों के बीच समन्वय और सत्यापन प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल संबंधित व्यक्तियों की पहचान और नागरिकता की पुष्टि को लेकर जांच और आधिकारिक प्रक्रिया जारी है, जबकि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

जापान में 5 हजार भारतीय रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर

टोक्यो (एजेंसी)। जापान में भारतीय रेस्टोरेंट उद्योग इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है। देशभर में संचालित करीब 5 हजार भारतीय रेस्टोरेंट बढ़ती लागत, सख्त नियमों और श्रमिकों की कमी के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जापान में लगभग 69 हजार भारतीय रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी हुई है। भारतीय और नेपाली समुदाय द्वारा संचालित ये रेस्टोरेंट जापानी शहरों में करी और मसालेदार व्यंजनों के लिए लोकप्रिय हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने विदेशी कर्मचारियों को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। पहले जहां कुशल विदेशी श्रमिकों को अपेक्षाकृत आसानी से वीजा मिल जाता था, वहीं अब स्थायी निवास और रोजगार संबंधी शर्तें सख्त हो गई हैं। इसके साथ ही रेस्टोरेंट मालिकों पर कर और प्रशासनिक खर्च का बोझ भी बढ़ा है। कई व्यवसायियों का कहना है कि कमाई घट रही है, जबकि किराया, वेतन और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय रेस्टोरेंट उद्योग में नेपाली कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन नए नियमों के कारण श्रमिकों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट सबसे अधिक दबाव में हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि सरकार ने राहत नहीं दी तो आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, जिससे हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और जापान में भारतीय खानपान की पहचान को भी झटका लग सकता है।

पश्चिम एशिया संघर्ष में चीन द्वारा ईरान की सैन्य मदद के नहीं मिले सबूत

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाउस एप्रोप्रियेशन्स सबकमेटी की सुनवाई में कहा कि अमेरिका को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि मौजूदा क्षेत्रीय संकट में चीन ने ईरान को सैन्य मदद की हो। रुबियो ने बताया कि उन्होंने बीजिंग से अपील की कि वह होर्मुज स्?ट्रेट में नौवहन खुलवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करें। रुबियो ने कहा कि मैं कहूंगा कि चीन ने ईरान को किसी भी तरह की सहायता नहीं दी है और न ही उसने हमारे अभियानों या हमारी काम करने की क्षमता में कोई बाधा डाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री ने माना कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण हैं और दोनों देशों के बीच लंबे समय से संबंध हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल के संघर्ष में चीन की ओर से ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी है जिससे युद्ध की स्थिति या सैन्य संतुलन पर कोई असर पड़ा हो। रुबियो ने चीन के रवैये को सावधानीपूर्ण बताया। उनका कहना था कि बीजिंग ने ईरान के साथ अपने व्यापक रणनीतिक संबंधों के बावजूद इस संकट में सीधे तौर पर शामिल होने से बचने की कोशिश की है। साथ ही रुबियो ने चीन से संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की, खासकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री यातायात में आ रही बाधाओं को दूर करने के प्रयासों में। रुबियो के मुताबिक अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है, जिसका उद्देश्य इस अहम समुद्री मार्ग में पैदा हुई स्थिति का समाधान करना है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। रुबियो ने कहा कि अगर वास्तव में वे जलडमरूमध्य को बंद किए जाने के खिलाफ हैं, तो उन्हें इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए या कम से कम इससे दूरी बनाते हुए वीटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए चीन के पास मजबूत आर्थिक कारण हैं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर काफी निर्भर है।

रुबियो के नए दावे से पलटी थ्योरी, जीवित हैं मोजतबा खामेनेई!

वॉशिंगटन (एजेंसी)। वॉशिंगटन(ईएमएस)। भीषण संघर्षविराम की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है, जो उसके अब तक के बयानों से बिल्कुल उलट है। अमेरिका अब तक लगातार यह कहता आया था कि मोजतबा खामेनेई अमेरिकी सैन्य हमले में मारे गए हैं या फिर वे इतने गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं कि अब सक्रिय नहीं हैं। हालांकि, अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि मोजतबा खामेनेई न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के बावजूद देश के प्रशासनिक और रणनीतिक फैसलों में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सामने बोलते हुए रुबियो ने स्पष्ट किया कि ऐसे पुख्ता संकेत मिले हैं कि खामेनेई पर्दे के पीछे से लगातार देश की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हैं और ईरान के सरकारी मामलों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के दौरान खामेनेई घायल हो गए थे, जिसके बाद से वे सार्वजनिक मंचों पर दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन का अब मानना है कि वे किसी सुरक्षित स्थान से एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों और अपने बेहद भरोसेमंद नेटवर्क के जरिये सरकारी कामकाज की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

रुबियो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम को स्थायी रूप देने की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन अब भी तेहरान के साथ किसी समझौते की संभावना देख रहा है और हालात कभी भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट शर्तों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ईरान प्रतिबंधों में राहत चाहता है, तो उसे हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना होगा और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पर से सभी प्रतिबंध या शुल्क हटाने होंगे। साथ ही ईरान को यह भरोसा देना होगा कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में सहयोग करेगा।

इसके अलावा, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर दीर्घकालिक सख्त सीमाओं को स्वीकार करे या यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया था कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने को लेकर जल्द कोई समझौता हो सकता है। हालांकि, ईरान ने फिलहाल मध्यस्थों के जरिए चल रही वार्ताओं को रोक रखा है। तेहरान का कहना है कि जब तक लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई बंद नहीं होती, तब तक किसी नई बातचीत का कोई औचित्य नहीं है।

कनाडा में भारत-पाकिस्तान से आने वाले आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि में हुआ सुधार

टोरंटो। कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटिजनशिप कनाडा ने नए आवेदनकर्ताओं के लिए प्रोसेसिंग टाइम की ताजा जानकारी दी है। पहले से तय समय से तुलना करने पर पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान से आने वाले कई आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि में सुधार हुआ है। वहीं, नाइजीरिया और अमेरिका से जुड़े कुछ आवेदन श्रेणियों में प्रतीक्षा अवधि बढ़ी है। वर्क परमिट आवेदनों में पाकिस्तान से आवेदन करने वालों के लिए प्रोसेसिंग टाइम 6 सप्ताह और भारत के लिए 9 सप्ताह किया गया है। कनाडा के अंदर से किए गए आवेदनों की प्रोसेसिंग 212 दिनों से घटकर 206 दिन हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया के आवेदकों को बड़ा झटका लगा है। वहां वर्क परमिट की प्रोसेसिंग अवधि 6 सप्ताह से बढ़कर 12 सप्ताह हो गई है। अमेरिका और फिलीपींस के लिए समय सीमा 5 और 8 सप्ताह है। स्टडी परमिट के मामले में भी पाकिस्तान के आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। वहां प्रोसेसिंग टाइम 11 सप्ताह से घटकर 7 सप्ताह कर दिया गया है। भारत के लिए यह अवधि 4 सप्ताह है। कनाडा के अंदर से किए गए स्टडी परमिट आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि 6 सप्ताह है। वहीं, नाइजीरिया में यह समय 5 सप्ताह से बढ़कर 6 सप्ताह हो गया है। अमेरिका और फिलीपींस के लिए प्रोसेसिंग टाइम 5 सप्ताह है। विजिटर वीजा आवेदनों में ज्यादातर देशों के लिए प्रोसेसिंग टाइम में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के लिए यह अवधि 28 दिन कर दी गई है। अमेरिका के लिए 25 और फिलीपींस के लिए 20 दिन कर दी गई है। कनाडा के अंदर से किए गए विजिटर वीजा आवेदनों का प्रोसेसिंग टाइम 11 दिनों से बढ़कर 16 दिन हो गया है। पाकिस्तान के लिए यह अवधि 50 दिनों पर स्थिर रही, जबकि नाइजीरिया में यह 47 दिनों से बढ़कर 48 दिन हो गई। सुपर वीजा श्रेणी में भारत और पाकिस्तान के आवेदकों को सबसे बड़ा फायदा मिला है। भारत के लिए प्रोसेसिंग टाइम 160 दिनों से घटकर 117 दिन कर दिया है। वहीं पाकिस्तान में यह अवधि 107 दिनों से घटकर 75 दिन कर दी है। इसके विपरीत, अमेरिका से किए गए सुपर वीजा आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि 103 दिनों से बढ़कर 115 दिन हो गई है। नाइजीरिया में यह समय 35 से बढ़कर 37 दिन हुआ, जबकि फिलीपींस में यह 32 दिनों पर स्थिर रहा।

आयोवा नरसंहार- आखिर सुपरपावर अमेरिका में क्यों नहीं थम रहा खूनी खेल?

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के आयोवा राज्य का मस्कटाइन शहर मंगलवार की सुबह अंधाधुंध गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमलावर ने खुद को भी उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक, यह खूनी खेल एक घरेलू विवाद का नतीजा था, जिसे 52 वर्षीय रायन विलिस मैकफारलैंड नामक शख्स ने अंजाम दिया। पार्क एवेन्यू के एक घर से शुरू हुआ मौत का यह सिलसिला मिल स्ट्रीट और ग्रैंडव्यू एवेन्यू तक जा पहुंचा। पुलिस ने जब संदिग्ध को घेरा, तो उसने खुद को गोली मार ली। पुलिस भले ही इसे घरेलू मामला बताकर पल्ला झाड़ ले कि अब समुदाय को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस भयावह घटना ने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है आखिर अमेरिका में बार-बार मास शूटिंग क्यों हो रही है?

हथियारों की सनक या कानून की लाचारी?

आयोवा का यह नरसंहार कोई इकलौती घटना नहीं है। यह अमेरिकी समाज में गहरे धंस चुके गन कल्चर की उस सड़ी हुई हकीकत को बयां करता है, जहां मामूली विवादों का निपटारा भी बंदूकों से किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका में हर नागरिक के पास घातक हथियार रखने का अधिकार तो है, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है? हर बड़ी घटना के बाद वहां गन कंट्रोल (हथियार नियंत्रण) पर बहस तो छिड़ती है, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। राजनीतिक नफा-नुकसान और हथियार लॉबी के दबाव के आगे अमेरिकी प्रशासन बेबस नजर आता है।

ओबामा की जिस डील पर ट्रंप भड़के थे अब उसी को अपना रहे राष्ट्रपति

-ईरान के साथ परमाणु समझौते पर चर्चा

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा रहा हो, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा की उतनी तीखी आलोचना की हो, जितनी 2015 की ईरान परमाणु डील को लेकर की थी। ट्रंप ने उस समय जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब समझौता बताया था। साल 2018 में राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने इस डील से अमेरिका को बाहर निकालकर इसे अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धियों में गिनाया था। लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि ईरान के साथ नए समझौते की कोशिशों में ट्रंप को उसी पुराने मॉडल का सहारा लेना पड़ सकता है, जिसे उन्होंने कभी पूरी दुनिया के सामने नाकाम और खतरनाक करार दिया था। यही वजह है कि अमेरिका में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि क्या ट्रंप वास्तव में कोई नई और मजबूत डील बना रहे हैं या सिर्फ पुराने समझौते को ही नए पैकेज में पेश करने की कोशिश हो रही है।

दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ चल रही मौजूदा बातचीत के कई बिंदु सीधे तौर पर ओबामा युग के जेसीपीओए की याद दिलाते हैं। प्रस्तावित समझौते में युद्धविराम बढ़ाने, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करने जैसी शर्तें शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन न करे और कभी परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी दे, जिसे तेहरान फिलहाल खारिज कर रहा है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने दावा किया था कि ओबामा प्रशासन ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस डील ने तेहरान को अरबों डॉलर दिए। लेकिन अमेरिका के पीछे हटने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया। जहां 2015 की डील के तहत ईरान केवल 3.67 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन कर सकता था, वहीं आज वह 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम जमा कर चुका है, जो हथियार-ग्रेड स्तर के बेहद करीब है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान वार्ता का पूरा ढांचा ओबामा युग की डील पर ही आधारित नजर आता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की बात जोड़ी जा रही है। जानकारों के मुताबिक, ट्रंप इस बात को लेकर बेहद चिंतित होंगे कि उनकी डील की तुलना ओबामा की डील से न की जाए, क्योंकि उस समझौते को खत्म करना उनके पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान थी। यदि नई डील में भी ईरान को प्रतिबंधों से राहत और जमे हुए अरबों डॉलर तक पहुंच मिलती है, तो ट्रंप के लिए अपने समर्थकों को यह समझाना मुश्किल होगा कि यह समझौता पुराने समझौते से किस तरह अलग और बेहतर है।

रूस ने यूक्रेन पर किया हमला, 23 की मौत, 90 घायल

– मिसाइल संकट ने बढ़ाई जेलेंस्की की चिंता

कीव (एजेंसी)। रूस ने मंगलवार देर रात यूक्रेन पर हाल के महीनों का सबसे बड़ा और विनाशकारी हवाई हमला किया है। सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों अत्याधुनिक मिसाइलों से कीव सहित पूरे देश को निशाना बनाया गया। इस भीषण हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेनी वायुसेना द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, रूस ने इस हमले में 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागीं। हालांकि, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 54 ड्रोन और 33 मिसाइलें सुरक्षा कवच को भेदने में कामयाब रहीं, जिससे कई इलाकों में आवासीय इमारतें जमींदोज़ हो गईं। इस हमले ने यूक्रेन की सबसे बड़ी सैन्य कमजोरी को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, जो कि पैट्रियट एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों की भारी कमी है।

पैट्रियट सिस्टम रूस की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सबसे अचूक माना जाता है, लेकिन यूक्रेन के पास इसकी बेहद सीमित संख्या है। राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने भी खुलकर स्वीकार किया कि मौजूदा हथियार आपूर्ति के सहारे वे इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से तुरंत सैन्य मदद की गुहार लगाई है।

पैट्रियट मिसाइलों की इस किल्लत के पीछे मुख्य वजह अमेरिका की सीमित उत्पादन क्षमता है। अमेरिका इस प्रणाली का मुख्य उत्पादक है, लेकिन उसकी सालाना उत्पादन क्षमता अभी सिर्फ 650 मिसाइलों के आसपास ही है। इसके अलावा, ईरान के साथ हालिया संघर्ष में अमेरिका और इजरायल द्वारा इन मिसाइलों का भारी इस्तेमाल किए जाने से वैश्विक स्टॉक और कम हो गया है। साथ ही, ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका पहले अपनी आंतरिक सुरक्षा जरूरतें पूरी कर रहा है, जिसके कारण यूक्रेन को आपूर्ति मिलने में देरी हो रही है। बदलते हालात के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस को पत्र लिखा है। अब तक यूक्रेन सीधे तौर पर तैयार हथियार मांग रहा था, लेकिन अमेरिका के पास घटते स्टॉक को देखते हुए अब जेलेंस्की ने मिसाइलों का प्रोडक्शन लाइसेंस मांगा है। यह कदम यूक्रेन की बढ़ती हताशा के साथ-साथ एक बड़े प्रतीकात्मक बदलाव को भी दिखाता है, जहां कभी हथियार मांगने वाला देश अब खुद निर्माण तकनीक की मांग कर रहा है। रूस इस स्थिति का फायदा उठाकर हमले तेज कर रहा है। यदि पश्चिमी देशों ने जल्द ही बड़े पैमाने पर मदद नहीं भेजी, तो यूक्रेन के शहरों पर तबाही का खतरा और गहरा सकता है।

कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने कर दिया हमला

कुवैत सिटी (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के कारण खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बीच एक बड़े घटनाक्रम में ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। इस दावे के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील हो गई है और कुवैत की सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। बुधवार को कुवैत के कई हिस्सों में अचानक तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने से हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुवैत की सेना के जनरल स्टाफ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की।

सेना ने पुष्टि की कि नागरिकों द्वारा सुनी गई धमाकों की आवाजें दरअसल उसके एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता के कारण थीं। कुवैती सैन्य अधिकारियों के अनुसार, देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसमान में ही दुश्मन की कई मिसाइलों और ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। कुवैत की सेना ने अपने बयान में कहा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस समय दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का कड़ा मुकाबला कर रहा है। यदि आगे भी धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं, तो जनता पैनिक न हो, क्योंकि वे दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए की जा रही जवाबी सैन्य कार्रवाई का ही परिणाम हैं।

इस हवाई कार्रवाई के बाद कुवैती सैन्य अधिकारियों ने नागरिकों और वहां रह रहे प्रवासियों के लिए एक सख्त एडवायजरी जारी की है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वे आसमान से गिरने वाले किसी भी मलबे, छर्रों या अज्ञात वस्तुओं के पास बिल्कुल न जाएं, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के दिखने पर तुरंत 112 आपातकालीन हॉटलाइन पर सूचित करें। साथ ही, उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ, ईरान के सरकारी मीडिया ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और केश्म द्वीप पर अमेरिका द्वारा की गई शत्रुतापूर्ण हरकतों का सीधा बदला है। हालांकि, इन हमलों में अमेरिकी ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल कुवैत की सेना पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।

700 मर्दों ने किया दुष्कर्म- ब्रिटिश सांसद ने संसद में बताया पीड़िताओं का दर्द

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन में कथित तौर पर सक्रिय रहे ग्रूमिंग गैंग और बाल यौन शोषण के मामलों को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाले और बेहद दर्दनाक खुलासे हुए हैं। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में दिए गए अपने संबोधन में कई पीड़िताओं की गवाहियों का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक संगठित गिरोहों ने नाबालिग लड़कियों का बेरहमी से यौन शोषण किया और इस पूरी अवधि के दौरान प्रशासनिक व संस्थागत स्तर पर भी गंभीर लापरवाहियां और विफलताएं देखने को मिलीं।

सांसद रूपर्ट लोव ने संसद के सामने इन मामलों को रखते हुए कहा कि एक स्वतंत्र जांच के दौरान जो गवाहियां सामने आईं, वे इतनी भयावह थीं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाना बेहद जरूरी था। उन्होंने संसद से पूरी ईमानदारी के साथ अपील की कि इन बहादुर पीड़िताओं की आवाज को अनसुना न किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सरकार की पूर्व जांच रिपोर्टों और इन गवाहियों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने वाले इन आपराधिक गिरोहों में मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के कुछ टैक्सी ड्राइवर और दुकानदार शामिल थे। संसद में पेश की गई इन गवाहियों में गंभीर यौन शोषण, बेहद कम उम्र में जबरन प्रेगनेंसी, डराने-धमकाने और स्थानीय पुलिस के कथित दुर्व्यवहार का ज़िक्र किया गया है। लोव ने कहा कि दुनिया को वह सब सुनना चाहिए जो स्वतंत्र रेप गैंग जांच की दो हफ्तों की सुनवाई के दौरान सामने आया है।

संसद में जो गवाहियां रखी गईं, उनमें से एक पीड़िता ने अपनी दर्दनाक आपबीती बताते हुए कहा कि जब वह महज 12-13 साल की थी, तब उसके साथ अमानवीय तरीके से जबरदस्ती की गई। वहीं, एक अन्य पीड़िता की गवाही के अनुसार, आरोपियों द्वारा नस्लवादी टिप्पणियां भी की जाती थीं। एक अन्य दिल दहला देने वाले बयान में पीड़िता ने दावा किया कि जब वह 13 साल की थी, तब से लेकर अगले तीन सालों के दौरान सैकड़ों अलग-अलग पुरुषों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। एक अन्य पीड़ित ने बताया कि बंधक बनाकर रखी गई लड़कियों को अमानवीय स्थितियों में पिंजरों तक में बंद करके रखा जाता था।

इस पूरे ग्रूमिंग गैंग पैटर्न की बात करें तो वर्ष 2025 में रूपर्ट लोव के नेतृत्व में हुई एक निजी जांच के दौरान पूरे यूके के कम से कम 85 इलाकों में इस तरह के गैंग आधारित बाल यौन शोषण की पहचान की गई थी। जांच रिपोर्टों के मुताबिक, इस नेटवर्क में एक खास पैटर्न और सरकारी संस्थाओं की घोर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ब्रिटेन में इस तरह के ग्रूमिंग गैंग्स का इतिहास पुराना रहा है। सबसे पहले 2002 में वेस्ट यॉर्कशायर के कीथली क्षेत्र से ऐसी चेतावनी सामने आई थी। इसके बाद साल 2010 में साउथ यॉर्कशायर के रॉदरहैम में कम उम्र की लड़कियों के साथ हुए अपराधों के मामले में एक समूह को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद इस पूरे संगठित नेटवर्क और इसके तौर-तरीकों का देशव्यापी खुलासा हुआ था।

पीएम मोदी के दमण दौरे को लेकर कचीगाम पंचायत सरपंच फाल्गुनी पटेल ने जगह-जगह आयोजित किया जनसंवाद बैठक

■ कचीगाम जिला पंचायत सदस्य हंसा धोडी, उपसरपंच जिग्नेश उकड पटेल, दमण जिला भाजपा प्रमुख भरत पटेल, जिला भाजपा महामंत्री गणेश पटेल, पंचायत सदस्यों नागरिकों की रही उपस्थिति

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून।

पीएम मोदी के दमण दौरे को लेकर गांव-गांव में नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपनी-अपनी पंचायतों में लगातार जनसंवाद बैठकें आयोजित कर नागरिकों को 5 जून को पीएम मोदी के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया है। कचीगाम ग्राम पंचायत सरपंच फाल्गुनी पटेल ने अपने पंचायत क्षेत्र में जनसंवाद बैठकों का आयोजन किया था। इस अवसर पर कचीगाम जिला पंचायत सदस्य हंसा धोडी, उपसरपंच जिग्नेश उकड पटेल, दमण जिला भाजपा प्रमुख भरत पटेल, जिला भाजपा महामंत्री गणेश पटेल, पंचायत सदस्यों नागरिकों की उपस्थिति रही। सरपंच फाल्गुनी पटेल ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी दमण की जनता को फिर एक बार कई सौगातें देने आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल का हमें साक्षी बनना है। बडी संख्या में 5 जून को स्वामी विवेकांनद ग्राउंड में उपस्थित रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन एवं स्वागत करना है। कचीगाम के नागरिकों ने उत्साहपूर्व बताया कि हम बडी संख्या में उपस्थित रहेंगे।

पीएम मोदी के प्रस्तावित दमण दौरे को लेकर 4 जून को होने वाली रिहर्सल के लिए पुलिस ने जारी की ट्रैफिक नियमों से जुडी सलाह

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 05 जून 2026 को दमण दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों और आमंत्रितों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी के तहत दमण पुलिस विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए 04 जून 2026 को एक रिहर्सल करेगा। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से ट्रैफिक नियमों से जूडी सलाह जारी की गई है। जिसके तहत मशाल चौक से भेसलोर चार रास्ता, नानी दमण बस स्टैंड से वड चौकी रोड, दलवाड़ा से मशाल चौक, मशाल चौक से तीन बत्ती, तीन बत्ती से मरवड, नमो पथ एवं छपली शेरी (नाइट मार्केट होते हुए) से धोबी तालाब तक का मार्ग 5 बजे से 8.30 बजे तक व्यस्त रहने की उम्मीद है। यात्रियों और आम जनता के लिए सलाह दी गई है कि वे 04 जून 2026 को शाम 5 बजे से 8.30 बजे तक उपरोक्त रास्तों का इस्तेमाल करने से बचें। कृपया अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा जारी किए गए सभी ट्रैफिक डायवर्जन और निर्देशों का पालन करें। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से किसी भी तरह की बहस न करें। ऊपर बताई गई सड़कों के किनारे वाहन पार्क न करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम और असुविधा हो सकती है। ट्रैफिक के सुचारू प्रबंधन और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक अधिकारियों के साथ सहयोग करें। यह सूचना दमण पुलिस विभाग द्वारा जनहित में जारी की गई है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत दमण कलेक्ट्रेट में मनाया गया तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून।

संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के प्रशासक प्रफुल पटेल के कुशल नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 02 जून 2026 को मोटी दमण कलेक्ट्रेट में तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर तेलंगाना क्षेत्र से संबंध रखने वाले और दमण जिले में निवास कर रहे गणमान्य व्यक्तियों को कलेक्ट्रेट में आईएएस अधिकारी सिद्धांत राजोरा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईएएस अधिकारी ने उपस्थित तेलंगाना राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विरासत पर गर्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अवसरों को मनाने से भाषा सीखने, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन, खान-पान, खेल और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने जैसे क्षेत्रों में निरंतर और सुव्यवस्थित सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

डीआईए ने 5 जून को पीएम मोदी के दमण आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए उद्योगजगत से की अपील

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। पीएम मोदी का 5 जून को दमण दौरा होने जा रहा है। दमण आगमन पर पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए डीआईए ने उद्योगजगत से अपील की है। डीआईए प्रेसिडेंट पवन अग्रवाल ने दमण के सभी उद्योगजगत से अनुरोध किया है कि 5 जून को पीएम मोदी के आगमन पर हजारों की संख्या में दमण कॉलेज ग्राउंड पर पहुंचकर पीएम मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करें। उन्होंने उद्योगजगत से अपील की है कि भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं।

स्वामी: मारुतिनंदन पब्लिक, संपादक, प्रकाशक व मुद्रक विजय जगदीशचंद्र भट्ट द्वारा गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल, नानी दमण - 396210 से प्रकाशित तथा असली आजादी प्रेस गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल नानी दमण - 396210 से मुद्रित।
(समाचारों के चयन के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी पीआरबी एक्ट के अंतर्गत संपादक की होगी। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र दमण न्यायालय के अधीन होगा।)

जवान के बाद अब सलमान की फिल्म में एक्शन का दम दिखाएंगी नयनतारा

विशेषज्ञों की निगरानी में करेंगी स्टंट सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान के अपोजिट साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा नजर आएंगी। शीर्षक फाइनल नहीं होने के चलते अस्थाई रूप से इस फिल्म को स्ङ्क्ष्59 कहा जा रहा है। फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें नयनतारा एक्शन पैक्ड अवतार में नजर आएंगी।

दमदार एक्शन करेंगी नयनतारा

इससे पहले नयनतारा को बॉलीवुड फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान के साथ देखा गया था। 'जवान' में भी नयनतारा का एक्शन देखने को मिला। उन्होंने अपने स्टंट से दर्शकों को हैरान कर दिया था। अब चर्चा है कि सलमान खान की आगामी फिल्म में भी वे दमदार एक्शन करती दिखेंगी। इससे फिल्म के प्रति दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है।

एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुद करेंगी स्टंट

मेकर्स की तरफ से फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नयनतारा इस फिल्म में एक मजबूत और दमदार किरदार निभाती हुई दिखेंगी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, नयनतारा एक्टर सलमान खान के साथ एक एक्शन से भरपूर रोल में नजर आएंगी। इसके अलावा, वे एक्सपर्ट्स की देखरेख में अपने स्टंट खुद ही करेंगी। ऐसा लगता है कि उनका किरदार काफी दमदार और अहम होने वाला है।

मनाली में चल रही शूटिंग

इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल मनाली में चल रही है, जहां एक महत्वपूर्ण शेड्यूल पर काम हो रहा है। एक्शन सीन्स के साथ-साथ, लीड जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री भी चर्चा का विषय बन रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान और नयनतारा के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। सलमान खान और नयनतारा के अलावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाएंगे।

कब रिलीज होगी फिल्म

आने वाले महीनों में इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर अनाउंसमेंट्स होने की उम्मीद है। मेकर्स इस फिल्म को ईद 2027 के मौके पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्में अक्सर त्योहारों के सीजन में ही रिलीज होती हैं। खासतौर से ईद के मौके पर वे दर्शकों को अपनी फिल्मों की रिलीज के रूप में तोहफा देते रहे हैं। इस फिल्म के अलावा सलमान वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि' में भी नजर आएंगे।

सोहम शाह ने शेयर की तुम्बाड 2 की डिटेल्स

सोहम शाह फिल्म 'तुम्बाड 2' की तैयारियों में व्यस्त हैं। यह फिल्म साल 2018 में आई 'तुम्बाड' का सीक्वल है। 'तुम्बाड 2' को लेकर दर्शक उत्साहित हैं और बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सोहम शाह ने सेट से एक बीटीएस तस्वीर शेयर करके दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ा दिया है। मगर, उनके इस पोस्ट पर नेटिजंस को आलिया भट्ट याद आ गई हैं। सोहम शाह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें सोहम शाह ने बीटीएस पल साझा किया है। उनके हाथ में सफेद रंग की एक चीज नजर आ रही है। इसके साथ सोहम शाह ने कैप्शन लिखा है, 'आज 'तुम्बाड 2' के सेट पर ये मिला। क्या मुझे चिंता करनी चाहिए' उन्होंने आगे लिखा है, 'प्रलय आएगी'।

सोहम शाह के इस पोस्ट पर नेटिजंस आलिया भट्ट को याद करते हुए कमेंट कर रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स इसे शुभ हस्ताक्षर और आशीर्वाद बता रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये आटे की गुड़िया लग रही है। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, 'आपको चिंता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छे के लिए'। आलिया को याद करते हुए एक यूजर ने लिखा है, 'आलिया को देखने के लिए बेसब्र हूं'। एक ने लिखा है, 'तुम्बाड-2 में आलिया हैं। अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि पूरा सिनेमा है'।

फिल्म 'तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट का कैमियो रोल होगा। वहीं, तीसरे पार्ट में उनका यह किरदार विस्तृत रूप में देखने को मिलेगा। साल 2018 में आई 'तुम्बाड' का निर्देशन राही अनिल बर्वे ने किया था। हालांकि, 'तुम्बाड 2' का निर्देशन वो नहीं कर रहे हैं। 'तुम्बाड 2' का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं। आदेश प्रसाद फिल्म के पहले पार्ट के को-राइटर और को-डायरेक्टर भी थे। फिल्म का निर्माण सोहम शाह अपने बैनर सोहम शाह फिल्म्स के तहत और पेन स्टूडियोज के सहयोग से कर रहे हैं। इस बार फिल्म में सोहम शाह के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे।

म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'सतरंगा' लाएंगे भूषण

टी-सीरीज एक बार फिर बड़े स्तर की म्यूजिकल फिल्म लेकर आने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूषण कुमार के नेतृत्व वाली कंपनी जल्द ही अपनी नई फिल्म 'सतरंगा' का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, यह फिल्म एक भव्य म्यूजिकल ड्रामा होगी, जिसे बड़े सिनेमाई कैनवास पर तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 'सतरंगा' सिर्फ एक पारंपरिक रोमांटिक फिल्म नहीं होगी, बल्कि इसमें संगीत कहानी की सबसे अहम कड़ी बनेगा। फिल्म को एक इमोशनल और विजुअली शानदार अनुभव के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है, जहां गाने केवल कहानी का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि पूरी कहानी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है और अब मेकर्स स्टारकास्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि, अभी तक किसी कलाकार के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

शिवा ट्रिलॉजी जैसी फिल्म का हिस्सा बनना मेरा सपना

फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार अब सिर्फ ग्लैमरस किरदारों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनमें अभिनय के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी हो। इसी बीच अभिनेत्री त्रिधा चौधरी ने आईएएनएस से बात करते हुए अपनी दिली इच्छा जाहिर की और कहा कि वह भविष्य में अभिनेता रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहती हैं। अगर उन्हें 'शिवा ट्रिलॉजी' जैसी किसी पौराणिक फिल्म में काम करने का मौका मिले, तो वह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा होगा। आईएएनएस ने जब त्रिधा से पूछा कि अगर उन्हें भविष्य में किसी बड़े ऐतिहासिक या पौराणिक फिल्म में काम करने का मौका मिले, तो वह किस तरह का किरदार निभाना पसंद करेंगी। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह लेखक अमिश त्रिपाठी की मशहूर किताब 'शिवा ट्रिलॉजी' पर बनने वाली फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी।

त्रिधा ने कहा, ''मैंने हाल ही में सुना है कि रणवीर सिंह ने 'शिवा ट्रिलॉजी' के फिल्मी राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने आगे कहा, 'भगवान शिव के प्रति मेरी गहरी आस्था है, और यही वजह है कि 'शिवा ट्रिलॉजी' से मेरा भावनात्मक जुड़ाव भी है। मैंने इस किताब की पूरी सीरीज पढ़ी है और कहानी ने मुझे काफी प्रभावित किया। अगर मुझे किसी ऐसी पौराणिक फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलता है, तो वह मेरे करियर का सबसे खास अनुभव होगा।' त्रिधा ने बातचीत के दौरान कहा, ''मेरे लिए सिर्फ खूबसूरत दिखना या ग्लैमरस किरदार निभाना ज्यादा मायने नहीं रखता। एक कलाकार की असली पहचान उसके अभिनय से होती है। अगर कोई कलाकार स्क्रीन पर सिर्फ अच्छा दिखे लेकिन अपने किरदार को सही तरीके से निभा न पाए, तो दर्शक उससे जुड़ नहीं पाते।''

तुषार कपूर ने अपने नए प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया, राजनीति पर बात की

तुषार कपूर बॉलीवुड के उन कलाकारों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कॉमेडी, ड्रामा और मल्टीस्टारर फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में बातचीत के दौरान उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया, राजनीति और आज की युवा पीढ़ी को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि आज का भारत पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है और सोशल मीडिया ने लोगों को राजनीति और देश के मुद्दों के प्रति काफी सतर्क बनाया है।

तुषार कपूर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा, ''मैं एक बार फिर दर्शकों के सामने कुछ नया लेकर आने के लिए बेहद उत्साहित हूं। यह मेरे लिए खास अनुभव है क्योंकि मैं लंबे समय बाद फिर उसी तरह के किरदार और माहौल में लौट रहा हूं। फिल्म का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी 10 से 15 दिनों की शूटिंग बाकी है।'' उन्होंने निर्देशक रोहित शेट्टी की जमकर तारीफ करते हुए कहा, ''मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे रोहित शेट्टी के साथ कई बार काम करने का मौका मिला। वह देश के सबसे सफल निर्देशकों में गिने जाते है। मैंने उनके साथ चार बार काम किया है और चारों बार फिल्मों को ब्लॉकबस्टर सफलता मिली। अब मुझे उम्मीद है कि पांचवीं बार भी दर्शकों का वैसा ही प्यार मिलेगा।''

तुषार कपूर ने सोशल मीडिया और राजनीति पर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ''पहले हमारी पीढ़ी राजनीति को इतना करीब से नहीं समझती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मैं खुद राजनीतिक बहस और न्यूज डिबेट्स को ध्यान से देखता हूं। आज मुझे देश के अलग-अलग राज्यों की राजनीति और वहां की पार्टियों की जानकारी है। सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने ज्यादा जागरूक बना दिया है। भारत में अब लोग राजनीति को गंभीरता से लेने लगे हैं। मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है क्योंकि लोग अब वोट देने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। साल 2014 के बाद देश में राजनीति को लेकर जागरूकता और ज्यादा बढ़ी है।तुषार ने कहा, ''आज की युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा काफी समझदार और जागरूक है।

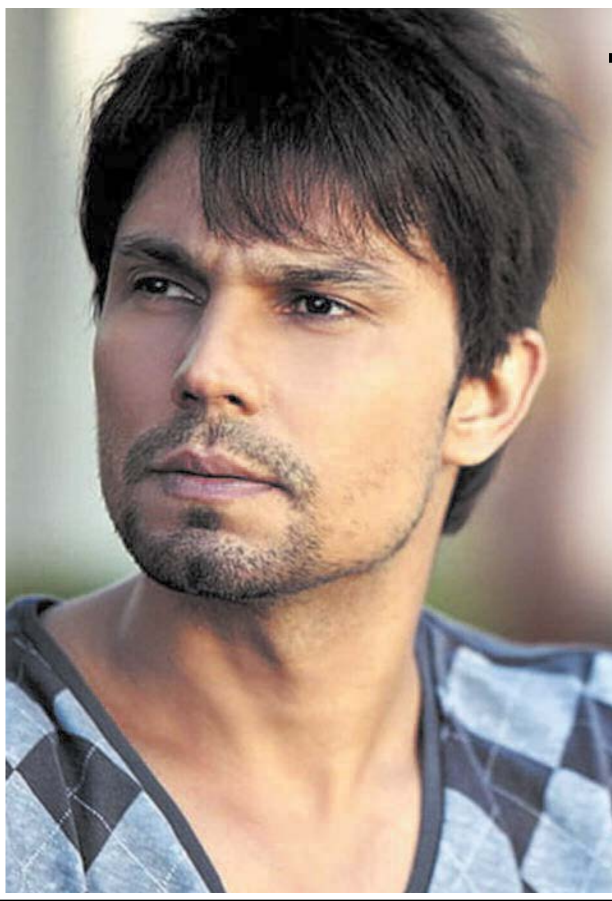

फादरहुड के बाद आए बदलाव अच्छे हैं

बात 'सरबजीत' और 'स्वातंर्त्य वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में हैरान कर देने वाले बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की हो या निजी जिंदगी में बेबाकी से अपनी राय रखने की, ऐक्टर रणदीप हुड्डा अपनी जिंदगी में हमेशा ही बेखौफ और रिस्क टेकर रहे हैं। कुछ हद तक अपनी हालिया सीरीज के हीरो 'इंस्पेक्टर अविनाश' की तरह, लेकिन अब यह आजाद परिंदा एक फैमिली मैन, एक नन्ही परी न्योमिका का पिता भी बन चुका है और रणदीप मानते हैं कि पिता बनने के बाद जिंदगी में काफी सारे सकारात्मक और सुखद बदलाव आते हैं।

फादरहुड के बाद खुद में आए बदलावों के बारे में रणदीप बताते हैं, 'बदलाव बिल्कुल आए हैं। लाइफ में थोड़ा ठहराव आ गया है। जिम्मेदारी का अहसास बढ़ गया है। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर एक अनकंडीशनल लव के बारे में सोचना और वह सोच खुद आपके अंदर आ जाती है। अब काम से घर जाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई है। एक विनम्रता आ गई है। दुनिया के प्रति भी सोच नरम हो गई है तो मेरे लिए बहुत ही समृद्ध करने वाला अनुभव है। हालांकि, अभी मैं वह अनुभव कर ही रहा हूं। अभी मैं नया-नया पिता बना हूं लेकिन निश्चित तौर पर काफी सारे पॉजिटिव बदलाव हैं। मैं खुद को इसके लिए बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं।'

डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पर मुझमें नहीं है

अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता और बिंदास एटीट्यूट के लिए मशहूर रहे रणदीप यह भी मानते हैं कि इंसान को जिंदगी में नाप-तौल को बोलना और बर्ताव करना यानी डिप्लोमेसी आनी चाहिए, मगर उनमें यह गुण नहीं है। बकौल रणदीप, 'आपके बेबाक और बिंदास होने के नुकसान भी होते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि आप जो नहीं हैं, वह बनकर रहने में ज्यादा मेहनत लगती है। फूंक-फूंक कर बोलने के चक्कर में आप एक झूठ बोलते हैं, फिर हजार झूठ बोलते हैं तो उससे बेहतर है कि सच पर ही रहो। जो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे वे करेंगे।'

कॉप के रोल से बच रहा था

रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के दूसरे सीजन को लेकर चर्चा में हैं। शो में वह यूपी के चर्चित कॉप इंस्पेक्टर अविनाश की भूमिका में काफी सराहे गए, मगर शुरू में उन्होंने यह रोल करने से ही मना कर दिया था। वजह पूछने पर वह बताते हैं, 'दरअसल, मैं कॉप का रोल करने से बच रहा था। मुझे लगा था कि मैं कॉप के किरदार कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं तो कहीं टाइपकास्ट ही ना हो जाऊं, मगर जब नीरज भाई (डायरेक्टर नीरज पाठक) ने कहानी सुनाई, तो मैं ना नहीं कर पाया।' वहीं, टाइप कास्टिंग के खतरे पर रणदीप आगे कहते हैं, 'टाइप कास्टिंग इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है, मगर चॉइस आपके हाथ में होती है कि आप खुद को दोहराना चाहते हैं या नहीं। कोई जबरदस्ती तो आपसे कुछ करा नहीं लेगा। मैंने काफी बार ऐसे रोल मना किए हैं, जो हाल ही किए होते हैं या उसमें मुझे नयापन नहीं लगता। वैसे, काम मना करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ऐक्टर का सबसे बड़ा काम ही काम पाना है। वरना उसके लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी लगती है जो सबके बस की बात नहीं है।'

राइटिंग में मजा आ रहा है

रणदीप ने अपनी फिल्म स्वातंर्त्य वीर सावरकर में निर्माता-निर्देशक की भूमिका भी निभाई थी। उस ओर आगे का प्लान पूछने पर उन्होंने बताया, 'बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि, जब मैं वीर सावरकर पूरी करके रिलीज कर रहा था, तब कान पकड़ लिया था कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आपको कभी न करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने दो स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। और भी लिख रहा हूं। मुझे राइटिंग में बहुत मजा आने लगा है। पहले क्या होता था कि जब बतौर ऐक्टर रोल आते थे तो हम करते थे, वरना काउच से बिस्तर और बिस्तर से काउच के बीच एक बड़ी लंबी जर्नी होती है। उसमें बहुत वक्त खाली बीतता था पर राइटिंग शुरू करने के बाद जब मैं ऐक्टिंग नहीं कर रहा होता हूं तब भी बहुत एक्साइटेड रहता है कि ऑफिस में जाकर कुछ लिख दूं, कुछ को-राइट कर लूं। कुछ फिल्म देख लूं तो बहुत कुछ करने का उत्साह रहता है जो सबसे बड़ी बात है।'

पीएम मोदी के दमण दौरे को लेकर भाजपा ने भेंसरोल ग्राम पंचायत में किया जनसंवाद कार्यक्रम, नागरिकों को दिया आमंत्रण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। पीएम मोदी के 5 जून को होने वाले दमण दौरे को लेकर आज भाजपा ने भेंसरोल ग्राम पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को पीएम मोदी के कार्यक्रम में बडी से बडी संख्या में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया। भेंसरोल ग्राम पंचायत सरपंच सविता पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा प्रभारी दुष्यंत पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेश आगरिया, महामंत्री जिग्नेश पटेल, दमण भाजपा अध्यक्ष भरत पटेल ने कार्यक्रम में बडी संख्या में उपस्थित नागरिकों को 5 जून को पीएम मोदी के आगमन के दौरान उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आमंत्रण दिया। साथ ही नागरिकों को पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए संकल्प भी दिलाया गया।

पीएम मोदी की दमण यात्रा पर पूर्व सांसद लालू पटेल ने पटलारा में किया जनसंवाद: नागरिकों को 5 जून को बडी संख्या में उपस्थित रहने का किया आह्वान

■ पटलारा सरपंच विजय पटेल, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य सतीष पटेल ने भी जनता को दिया आमंत्रण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। पीएम मोदी की 5 जून को होने वाली प्रस्तावित दमण यात्रा को लेकर पूर्व सांसद लालू पटेल ने आज पटलारा के विभिन्न क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर जनसंवाद किया। इस अवसर पर पटलारा ग्राम पंचायत के सरपंच विजय पटेल, पटलारा जिला पंचायत के पूर्व सदस्य सतिष पटेल भी उपस्थित रहे। पूर्व सांसद लालू पटेल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने जनसंवाद के माध्यम से 5 जून को होने वाले पीएम मोदी के दमण दौरे के कार्यक्र में बडी संख्या में शामिल होने के लिए नागरिकों को आमंत्रण दिया। साथ ही नागरिकों को बताया कि पीएम मोदी प्रदेशवासियों को कई बडी सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि बडी संख्या में उपस्थित रहकर पीएम मोदी का स्वागत एवं अभिवादन करें। ग्रामीणों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए अपना पूरा उत्साह दिखाया।

पीएम मोदी के दमण आगमन को लेकर दिलीपनगर में हुआ जनसंवाद कार्यक्रम

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 5 जून को दमण दौरा होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में दिलीपनगर में भाजपा द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीडीए चेयरमैन लखम टंडेल के नेतृत्व में आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेश आगरिया एवं दमण जिला भाजपा अध्यक्ष भरत पटेल सहित बडी संख्या में दिलीपनगर सोसायटी के निवासियों की उपस्थिति रही। इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी के कार्यक्रम में बडी संख्या में नागरिकों को उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया गया। पीएम मोदी के 5 जून को होने वाले दमण दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी उपस्थित नागरिकों ने संकल्प भी लिया।

पीएम मोदी के दमण दौरे को लेकर घेलवाड ग्राम पंचायत में विशेष जनसंपर्क अभियान के साथ चलाया गया सफाई अभियान

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। 5 जून को पीएम मोदी के होने वाले दमण दौरे को लेकर घेलवाड ग्राम पंचायत में विशेष जनसंपर्क अभियान के साथ सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत घेलवाड ग्राम पंचायत सरपंच हिताक्षी पटेल, जिला पंचायत सदस्य अशोक पटेल और ग्राम पंचायत सदस्यों तथा ग्रामीणों ने घर-घर जाकर नागरिकों को पीएम मोदी के कार्यक्रम में बडी संख्या में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। इस दौरान नागरिकों से बही संख्या में उपस्थित रहकर पीएम मोदी का स्वागत करने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील भी की गई। इसके साथ ही घेलवाड ग्राम पंचायत के विभिन्न रास्तों, सार्वजनिक स्थलों एवं आस-पास के विस्तारों की सफाई करके स्वच्छ एवं सुंदर गांव का संदेश दिया गया।

पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मरवड ग्रुप ग्राम पंचायत की टीम ने नागरिकों को दिया आमंत्रण

■ मरवड ग्रुप ग्राम पंचायत सरपंच रमेश (सोमा) पटेल, जिला पंचाय सदस्य धर्मिष्ठा पटेल, उपसरपंच शीतलबेन पटेल एवं पंचायत सदस्यों ने नमो पथ दरिया किनारे व्यवसाय करने वाले लोगों और घर-घर जाकर नागरिकों को दिया आमंत्रण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। पीएम मोदी के दमण दौरे को लेकर मरवड ग्रुप ग्राम पंचायत ने जनसभा, जनसंवाद के साथ-साथ घर-घर जाकर नागरिकों को आमंत्रण दिया। इस अवसर पर मरवड ग्रुप ग्राम पंचायत सरपंच रमेश (सोमा) पटेल, जिला पंचाय सदस्य धर्मिष्ठा पटेल, उपसरपंच शीतलबेन पटेल, पंचायत सदस्यों दिलीप रमण, विरांगी जयंती, मासूम धनसुख पटेल, जयश्री चंद्रकांत माह्यावंशी, बेनाबेन हलपति, गीताबेन केशव पटेल, मनोज बाबू पटेल एवं विजय हीरा टंडेल ने नमो पथ समुद्र किनारे व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को आमंत्रण पत्र दिया। इसके साथ ही घर-घर जाकर ग्रामीणों को आमंत्रण पत्र देकर पीएम मोदी के कार्यक्र में बडी से बडी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं दमण में हुए सर्वांगीण विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए 5 जून को होने वाले पीएम मोदी के दौरे में बडी संख्या में शामिल होकर उनका अभिवादन करने के लिए आमंत्रण दिया।

पीएम मोदी के दौरे को लेकर डीएमसी वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पटेल ने मशाल चौक एवं आस-पास के क्षेत्रों में नागरिकों के घर-घर जाकर दिया आमंत्रण

■ डीएमसी वॉर्ड नं. 11 में मुकेश पटेल ने जनसंवाद भी किया और सफाई अभियान भी चलाया

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 03 जून। पीएम मोदी के 5 जून को प्रस्तावित दमण दौरे को लेकर डीएमसी वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पटेल ने मशाल चौक एवं आस-पास की क्षेत्र की बिल्डिंगों एवं सोसायटियों में नागरिकों के घर-घर जाकर आमंत्रण दिया। मुकेश पटेल ने अपने वॉर्ड नं. 11 में जगह-जगह ग्रुप मीटिंग के जरिये जनसंवाद करते हुए युवाओं और नागरिकों को बडी संख्या में 5 जून के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण दिया। डीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पटेल ने अपने वॉर्ड विस्तार में स्वच्छता अभियान भी चलाया।

स्वामी: मारुतिनंदन पब्लिक, संपादक, प्रकाशक व मुद्रक विजय जगदीशचंद्र भट्ट द्वारा गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल, नानी दमण - 396210 से प्रकाशित तथा असली आजादी प्रेस गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल नानी दमण - 396210 से मुद्रित।
(समाचारों के चयन के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी पीआरबी एक्ट के अंतर्गत संपादक की होगी। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र दमण न्यायालय के अधीन होगा।)